● वर्ष-5

● अंक-290

रायपुर, बुधवार
22 जुलाई 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार



पेज-8>> मुख्यमंत्री से अभा सेवाओं में ...

दोनों सदनों में हंगामा और सड़क पर प्रदर्शन



छात्रों पर लाठीचार्ज-नीट पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा

नई दिल्ली। मानसून सत्र के दूसरे दिन भी विपक्षी दलों ने संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा किया और सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी। इस दौरान दोनों सदनों की कार्यवाही को दो बार थोड़े- थोड़े समय के लिए और तीसरी बार पूरे दिन भर के स्थगित कर दिया गया।

हालांकि दूसरे दिन विपक्षी दलों के मुद्दे बदले हुए थे। जिसमें से श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा गायब था, उसकी जगह छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पेपर लीक के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने की कोशिश की गई है लेकिन जोरदार हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही जब-जब शुरू हुई, उसे तुरंत ही स्थगित कर दिया गया।

विपक्ष का जोरदार हंगामा

दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे की शुरूआत मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरु होते ही 11 बजे हुई। जिसके चलते दोनों सदन को पहले 12 बजे तक के लिए और बाद में दो बजे तक के लिए स्थगित किया गया। लेकिन दो बजे जैसे ही सदन फिर बैठा, विपक्ष सदस्य शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे।

सदन दिन भर के स्थगित

इसके बाद तो सदन को दिन भर के स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे को उठाते हुए सरकार पर नाराजगी जतायी।

लोकसभा में हंगामा

वहीं लोकसभा में भी कांग्रेस, सपा सहित दूसरे विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष से नीट पेपर लीक पर चर्चा कराने की मांग की।

नीट पेपर लीक पर चर्चा हो- खरगे

वहीं सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद बाहर आए कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कहा कि 'हम चाहते हैं कि सदन में नीट पेपर लीक पर चर्चा हो। छात्रों पर क्यों लाठीचार्ज किया गया, इस पर सरकार जवाब दे, उन्होंने कहा कि ' सरकार खुद उकसा रही है कि देश में अराजकता हो और लाठीचार्ज किया जाए। लोगों को मारा जाए।

दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन के बाद नीट पेपर लीक पर बोले पीएम मोदी, कहा- दोषियों के लिए चाहते हैं कड़ी से कड़ी सजा

नईदिल्ली। संसदीय दल की बैठक में नीट परीक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक की खबरों के बाद सरकार ने तेज़ी से कार्रवाई की, 13 आरोपियों को गिरफ़्तार किया और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए दोबारा परीक्षा कराने को प्राथमिकता दी गई। यह बात पीएम मोदी ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' के नेतृत्व में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग को लेकर संसद की ओर मार्च करने के एक दिन बाद कही।

एनडीए की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, नीट परीक्षा के मामले में, प्रधानमंत्री ने बताया कि पेपर लीक की खबरें सामने आते ही सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो, नीट की दोबारा परीक्षा को प्राथमिकता दी गई, इसे सफलतापूर्वक आयोजित किया गया और बिना किसी देरी के नतीजे घोषित कर दिए गए। रिजिजू ने आगे कहा, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भविष्य में पेपर लीक की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। पेपर लीक रैकेट में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उन्होंने अपील की कि देश के शीर्ष वकीलों की मदद से उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि ऐसे गंभीर अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ मिसाल कायम करने वाली कार्रवाई हो और ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।अपनी मांगों को मनवाने के लिए देश भर से हजारों प्रदर्शनकारी सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और मानसून सत्र के पहले दिन संसद की ओर मार्च किया। जब वे दिल्ली के बीचों-बीच जमा हुए



तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे हिंसा भड़क गई। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसमें 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों समेत 200 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस ने पांच एफआईआर दर्ज कीं और इस बात की जांच शुरू की कि क्या यह हिंसा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शांति भंग करने की किसी बड़ी साज़िश का हिस्सा थी।

पीएम हाउस के बाहर राहुल के धरने पर भड़की आप

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा। पार्टी ने गृह मंत्री से संसद में बयान और चर्चा की मांग दोहराते हुए पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी उठाई। कांग्रेस के इस धरने पर आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए अपने ट्वीट में लिखा, सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया। राहुल गांधी के धरना प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए संजय सिंह ने कहा कि, देश के करोड़ों युवाओं के लिए सोनम वांगचुक जी पिछले 23 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। जंतर मंतर पर देश का युवा आंदोलन कर रहा है। 20 जुलाई को युवाओं को बर्बरता पूर्वक पीटा गया। कांग्रेस एक महीने से आंदोलन को गाली दे रही है, अब राहुल गांधी जी कह रहे है जंतर मंतर नहीं हमारे धरने में शामिल हो।

पीएम आवास के सामने धरने पर बैठे राहुल -प्रियंका को पुलिस ने हिरासत में लिया

नईदिल्ली। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के सामने कांग्रेस सांसद, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में धरने पर बैठे थे। हालांकि कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं और बसों में कांग्रेस नेताओं को भरकर पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है।

कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, यह अंत नहीं है। यह राहुल गांधी के नेतृत्व में एक नई क्रांति की शुरुआत है। वे हमें जेल में डाल सकते हैं, लाठीचार्ज कर सकते हैं, या हमारे साथ बुरा बर्ताव कर सकते हैं, लेकिन मोदी जी को भारत के उन लाखों बेटे-बेटियों को जवाब देना होगा जिन्होंने अपना भविष्य खो दिया है और पेपर लीक के कारण अपने परिवारों की उम्मीदें खत्म होते देखी हैं। यह क्रांति अब एक बड़ी आग बनेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में, इसे रोका नहीं जा सकेगा।



राहुल गांधी ने लोगों से अपने प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी देशभक्त भारतीय हमारे धरने में शामिल हों। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों पर हमला हर एक भारतीय परिवार पर हमला है और छात्रों की आवाज दवाई नहीं जा सकती।

जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपनी बात से मुकर गए। जितेंद्र सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, कुछ समय पहले, यह ज्ञात हुआ कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके साथ अन्य वरिष्ठ नेता, जैसे कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इत्यादि अकस्मात ही अकबर रोड़ के समीप एक स्थान पर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गये हैं। सरकार ने इस वरिष्ठ दल की गरिमा के दृष्टिगत, मुझे स्वंय और मेरे साथ केंद्रीय गृह सचिव, गोविंद मोहन को इन वरिष्ठ नेताओं से वार्ता करने हेतु मौके पर भेजा। श्री राहुल गांधी से अनुरोध किया गया कि वे अपना धरना समाप्त करें, क्योंकि यह स्थल धरने का स्थल नहीं है, और यहां पर धरना करने से जनसाधारण को काफी असुविधा भी पहुंच रही है। राहुल गांधी जी ने यह मांग रखी कि यदि सरकार संसद में नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए मान जाती है।

जंतर-मंतर पर फिर शुरू हुआ सीजेपी का प्रदर्शन

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का जंतर-मंतर पर आंदोलन दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदर्शन स्थल खाली कराए जाने के कुछ ही घंटों बाद एक बार फिर शुरू हो गया। सोमवार शाम करीब पांच बजे पुलिस ने संसद मार्च के बाद प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर से हटाया था, लेकिन लगभग छह घंटे बाद देर रात प्रदर्शनकारी दोबारा लौट आए और अस्थायी मंच तैयार कर आंदोलन फिर से शुरू कर दिया। रात 11 बजे तक बड़ी संख्या में समर्थक जंतर-मंतर पर जुट गए



और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे।

सीजेपी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने कहा कि आंदोलन फिलहाल समाप्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंगलवार को भी संसद की ओर मार्च किया जाएगा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक धरना जारी रहेगा। उनके अनुसार, प्रदर्शनकारी अपनी तीन प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और जब तक इन मांगों पर सरकार सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, तब तक वे जंतर-मंतर से हटने वाले नहीं हैं। सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले बड़ी संख्या में समर्थकों ने संसद की ओर मार्च किया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों का जत्था संसद परिसर के प्रवेश द्वार तक पहुंच गया। इसे सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना माना जा रहा है।

प्रमुख समाचार

सीजेपी प्रदर्शन में घायल लोगों से मिलने अस्पताल पहुंचे नड्डा

नईदिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को राजधानी के राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया। वे सोमवार को सीजेपी के विरोध मार्च के बाद पुलिस की कार्रवाई में घायल हुए लोगों से मिलने गए थे। नड्डा अस्पताल पहुंचे और विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल होने के



बाद इलाज के लिए भर्ती लोगों से बातचीत की। अपने दौरे के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने डॉक्टरों के साथ बैठक भी की ताकि घायलों की हालत और उन्हें दी जा रही मेडिकल देखभाल का जायजा ले सकें। इलाज की व्यवस्थाओं का जायजा लेने और घायलों से मिलने के बाद नड्डा अस्पताल से चले गए। नड्डा के अलावा, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। सोमवार को संसद की ओर सीजेपी का विरोध मार्च हिंसक हो गया था। दिल्ली पुलिस का दावा है कि झड़पों में 118 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। साथ ही, लगभग 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है।

छात्रों पर पुलिस कार्रवाई, राहुल ने अमित शाह का मांगा इस्तीफा

नईदिल्ली। नई दिल्ली में सोमवार को प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि दिल्ली में प्रदर्शनकारी



छात्रों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, उसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं और उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस गंभीर मामले पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आगे आकर छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी साझा किया कि वह पुलिस कार्रवाई में घायल हुए छात्रों से मुलाकात करने भी जाएंगे। विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष से मांग की कि छात्रों से जुड़े इन संवेदनशील मुद्दों पर सदन के भीतर विस्तार से चर्चा कराई जाए। अपनी इस मुलाकात के बारे में बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से चर्चा कराने का अनुरोध किया, जिस पर अध्यक्ष ने जवाब दिया कि इस संबंध में उन्हें पहले सरकार से बात करनी होगी।

पेपर लीक पर अखिलेश यादव का सरकार पर बड़ा हमला

नईदिल्ली। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने मंगलवार को केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने पेपर लीक के कथित मामले और राजधानी में सीजेपी के विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और कहा कि परीक्षाओं की शुचिता



बनाए रखना सरकार की ज़िम्मेदारी है। संसद में पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने कहा कि सरकार पेपर लीक रोकने में नाकाम रही है और उन्होंने सत्ताधारी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। यादव ने कहा, यह सुनिश्चित करना सरकार की ज़िम्मेदारी है कि पेपर लीक न हों। इतनी बड़ी गड़बड़ी के बाद भी सदन में नारे लग रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? सरकार की लाठियों से युवाओं और छात्रों के सिर फोड़े जा रहे हैं, आप आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं, आप बिजली के झटके दे रहे हैं। क्या यही सबका साथ, सबका विकास है? क्या यही अमृत काल है? जवाबदेही की मांग को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए यादव ने आरोप लगाया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राजनीतिक कारणों से इस्तीफ़ा नहीं दिया है।

शिवसेना (यूबीटी) ने स्पीकर के विलय वाले फैसले को दी चुनौती

मुंबई। शिवसेना ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के उस फ़ैसले को चुनौती दी, जिसमें उन्होंने पार्टी के छह सांसदों के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को मंज़ूरी दी थी। शिवसेना की ओर से सीनियर वकील देवदत्त



कामत ने चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच के सामने यह मामला रखा। कामत ने बेंच से गुज़ारिश की कि इस याचिका पर सुनवाई के लिए बुधवार को लिस्ट किया जाए। सीजेआई ने कहा कि हम देखेंगे। कामत ने बेंच को बताया कि 18 जुलाई को स्पीकर ने शिवसेनाके छह सांसदों के शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को मंज़ूरी दी थी। स्पीकर ने विलय को मान्यता दे दी है। उन्होंने आगे कहा कि यह एक राष्ट्रीय घटना बन गई है क्योंकि सांसद अब उन लोगों के साथ मिल रहे हैं जिनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। मानसून सत्र से पहले, 18 जुलाई को ओम बिरला ने शिवसेना के छह सांसदों के शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को मंज़ूरी दे दी।

कोलकाता में ममता बनर्जी ने की बड़ी रैली

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बिड़ला तारामंडल में 21 जुलाई शहीद दिवस रैली आयोजित की। यह रैली 1993 में लेफ्ट फ्रंट सरकार के दौरान एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में मारे गए यूथ कांग्रेस के 13 कार्यकर्ताओं की याद में की गई थी।



शहीद दिवस कार्यक्रम के लिए टीएमसी समर्थक कोलकाता में जमा हुए, और एक समर्थक ने पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर भरोसा जताया। समर्थक ने कहा टीएमसी फिर जीतेगी। मैं दीदी का समर्थन करता हूं। इस बीच, शहीद दिवस पर कोलकाता में बोलते हुए टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने 1993 की घटना को याद किया और बताया कि उस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व ममता बनर्जी ने किया था। रॉय ने मीडिया को बताया उस समय, ममता बनर्जी के नेतृत्व में वोटर पहचान पत्र की मांग को लेकर निकाले जा रहे जुलूस पर कोलकाता में सरकारी पुलिस ने फायरिंग की थी। इसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी और 200 लोग घायल हुए थे। ममता बनर्जी तब से ही उस घटना की याद में शहीद दिवस मनाती आ रही हैं।

कानून नहीं, नागरिकों की चेतना करती है आजादी की असली रक्षा

ब्रेट स्टीफेंस

सन 1944 के मई महीने में न्यूयार्क में न्यायमूर्ति लर्नड हैंड ने 'स्वतंत्रता के मर्म' पर एक संक्षिप्त, किंतु कालजयी भाषण दिया। उन्होंने चेताया था कि स्वतंत्रता की रक्षा केवल संविधान, कानून या न्यायालय नहीं कर सकते। और जहां मनुष्य अपनी स्वतंत्रता पर किसी मर्यादा को स्वीकार नहीं करता, वहां अंतत: स्वतंत्रता कुछ हिंसक और स्वार्थी लोगों की जागीर बन जाती है।

उनके अनुसार, स्वतंत्रता की आत्मा विनम्रता, जिज्ञासा, उदारता और आत्मसंयम के संगम में बसती है। वह उस मन की अवस्था है, जो अपने ही सत्य पर अभिमान से अडिग नहीं रहता, जो दूसरों के विचारों को समझने का प्रयास करता है, जो अपने हितों के साथ दूसरों के हितों को भी समान निष्पक्षता से तौलता है। यह कोई स्थिर उपलब्धि नहीं, बल्कि एक दुर्लभ चेतना है, जिसे केवल नागरिकों का विवेक और साहस ही जीवित रख सकता है। उसी चेतना की रक्षा के लिए उस समय असंख्य युवा अपने प्राण न्योछावर कर रहे थे।

यह भाषण डी-डे की पूर्व संध्या पर दिया गया था। आज जब अमेरिका अपनी ढाई सौवीं वर्षगांठ के जश्न में डूबा है, तब फिर वही प्रश्न सामने खड़ा है कि स्वतंत्रता की मूल भावना क्या है या वास्तव में क्या होनी चाहिए?

यह भावना है सार्वजनिक आदर्श की, जिसकी शुरुआत राष्ट्र प्रमुख के चरित्र से होती है। एक ऐसा मर्यादित चरित्र, जो विनम्रता, संयम और शुचिता से ओत-प्रोत हो। वे गुण, जो इस सर्वोच्च पद की असीम और कभी-कभी भयावह शक्तियों को संतुलित करने के लिए नितांत आवश्यक हैं। यह भावना है एक ऐसे नेतृत्व की, जो स्वयं को पूर्णत:, पारदर्शी रूप से और सूक्ष्मता के साथ नियम के अधीन रखकर कानूनों का निष्ठापूर्वक पालन सुनिश्चित करता है। यह भावना है एक ऐसी राज कुशलता की, जो कभी आडंबर को महानता, लफ्फाजी को यथार्थ या स्मारकों को सार्थकता समझने की भूल नहीं करती।



यह भावना है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की, इस बोध की कि लोकतांत्रिक विकल्प चुनने का अधिकार हमसे यह मांग करता है कि हम अपने निर्णयों की जिम्मेदारी स्वयं लें, न कि बलि के बकरे तलाशें। यह भावना है विक्टिम मेंटालिटी के प्रति तिरस्कार की, जो एक स्वतंत्र समाज को शोभा नहीं देती और उसके चरित्र का पतन करती है। यह इस दृढ़ विश्वास की भावना है कि कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र, जो सफलता का श्रेय तो लेता है, परंतु असफलता की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेता है। वह न तो सफलता के योग्य है और न ही अपनी भूलों को दोहराने से बच सकता है।

स्वतंत्रता की आत्मा इतिहास की स्मृति से भी जन्म लेती है। यदि हम यह भूल जाएं कि स्वतंत्रता पाने के लिए कितने संघर्ष, कितने बलिदान और कितनी पीढ़ियों की तपस्या लगी है, तो उसे बचाए रखना भी संभव नहीं होगा। इतिहास का सम्मान न तो आंख मूंदकर नायकों की पूजा करना है और न ही हर पूर्वज को कठघरे में खड़ा कर देना। बुद्धिमत्ता इस बात में है कि हम उनके योगदान को समझें, उनकी सीमाओं को भी पहचानें और उस व्यवस्था की मजबूती को संजोएं, जिसने आने वाली पीढ़ियों को स्वयं को और बेहतर बनाने का अवसर दिया।स्वतंत्रता का स्वभाव खुलापन है। खुला हाथ, जो उदारता से आगे बढ़े। खुला द्वार, जो योग्य लोगों का स्वागत करे और खुला मन, जो नए विचारों का स्वागत कर सके। यह आत्मविश्वास भी उसी का हिस्सा है कि उदार बने रहते हुए भी कोई समाज अपनी सीमाओं, सुरक्षा और मूल विश्वासों की रक्षा कर सकता है। ऐसा समाज स्वयं का उत्सव मनाने से अधिक स्वयं का आत्मपरीक्षण करता है। वह पुराने विशेषाधिकारों को केवल उनकी उम्र के कारण महत्व नहीं देता, बल्कि नए विचार, नई प्रतिभा और नए नागरिक का भी समान सम्मान करता है।

आर्थिक जीवन में भी यही खुलापन उद्यम, सृजन और श्रम को सम्मान देता है, जिससे समृद्धि जन्म लेती है और परोपकार के नए मार्ग खुलते हैं। स्वतंत्रता की आत्मा यह भी जानती है कि संसार में उसके विरोधी हैं। उनसे संघर्ष केवल शक्ति के बल पर नहीं, बल्कि विश्वसनीय मित्रताओं, धैर्य और सिद्धांतों के प्रति निष्ठा से जीता जाता है। नेतृत्व वही कर सकता है, जो पहले स्वयं नेतृत्व के योग्य सिद्ध हो। जो समाज स्वतंत्रता का आदर्श प्रस्तुत करता है, उसके विरोधी अक्सर उसकी त्रुटियों से अधिक उसके आदर्शों से भयभीत होते हैं, क्योंकि वही आदर्श उनके अपने उत्पीड़ित नागरिकों को आशा देते हैं।स्वतंत्रता का सबसे बड़ा शत्रु केवल हथियार उठाने वाला उग्रवादी नहीं होता। वह हर वह व्यक्ति भी है, जो विचारों पर पहरा बैठाना चाहता है। जो यह तय करना चाहता है कि कौन-सा विचार वर्जित है और कौन-सा शब्द बोलना अपराध है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उद्देश्य केवल श्रेष्ठ विचारों की रक्षा करना नहीं, बल्कि उन विचारों की भी रक्षा करना है, जो गलत सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि अनेक बार भूल ही सत्य तक पहुंचने का पहला सोपान बनती है।

नारायणपुर में सीपीआई का विरोध प्रदर्शन



धर्म स्वतंत्रता विधेयक के खिलाफ उठाई आवाज

नारायणपुर। बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में मंगलवार को सीपीआई ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। सीपीआई ने भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के बैनर तले 12 सूत्रीय मांगों को लेकर हल्ला बोला है। आंदोलन में बड़ी संख्या में ग्रामीण और समर्थक शामिल हुए।

प्रदर्शनकारियों ने संविधान विरोधी बताए जा रहे कानूनों और निर्णयों को वापस लेने, धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने की मांग की है। इसके अलावा मॉब लिंचिंग और कथित फर्जी गौकशी के नाम पर होने वाली हत्याओं पर रोक लगाने की भी मांग की है। छत्तीसगढ़ में हाल ही में लागू किए गए धर्म स्वतंत्रता विधेयक के विरोध में भी जमकर नारेबाजी की गई।

वहीं ईवीएम के विरोध में भी प्रदर्शनकारियों ने अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों ने रैली निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन जताया। सभी रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने की बात कही। नारायणपुर के बाजार स्थल पर आयोजित इस आंदोलन में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी रही। भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के बैनर तले आयोजित धरना-प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथों में विभिन्न मांगों से संबंधित बैनर और पोस्टर लेकर नारेबाजी की। पूरे प्रदर्शन स्थल पर मॉब लिंचिंग बंद करो, मूल निवासियों पर अत्याचार बंद करो और फाइट फॉर जस्टिस जैसे नारे गूंजते रहे। आंदोलनकारियों ने 18 सूत्रीय मांगों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देश में संविधान की मूल भावना और नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान संविधान के अनुच्छेद 25 से 29 तक धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बिंदु छत्तीसगढ़ में हाल ही में लागू किए गए धर्म स्वतंत्रता विधेयक का विरोध रहा। प्रदर्शनकारियों ने इस कानून को धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की।

आंदोलनकारियों का आरोप है कि धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर प्रदेश में विवाद और सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने ऋस्स और बजरंग दल जैसे संगठनों पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि धर्मांतरण के मामलों को लेकर विवाद, आपसी झगड़े और सामाजिक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

प्रदर्शनकारियों ने मॉब लिंचिंग और कथित तौर पर गौकशी के नाम पर होने वाली हत्याओं को लेकर भी विरोध जताया।

धरना प्रदर्शन के दौरान कई कानूनी प्रावधानों और निर्णयों को संविधान विरोधी बताते हुए उन्हें वापस लेने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने संविधान की मूल भावना, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की मांग उठाई।

दिल्ली के छात्र आंदोलन के समर्थन में निकली विशाल रैली



प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की उठाई मांग

गरियाबंद। दिल्ली में जारी छात्र आंदोलन के समर्थन में गरियाबंद जिले के मैनपुर तहसील मुख्यालय में छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विशाल रैली निकालकर प्रदर्शन किया। बारिश के बीच निकली इस रैली में बड़ी संख्या में छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सोनम वांगचुक के समर्थन में आवाज बुलंद करते हुए लोकतांत्रिक आंदोलनों के पक्ष में अपनी बात रखी। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई।

रैली के बाद प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के नाम मैनपुर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि देश के छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है।

बारिश के बावजूद प्रदर्शन में शामिल लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। रैली के दौरान छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी मांगें जोरदार तरीके से रखीं।

पूर्व एएनएम ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप



मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। जिले में स्वास्थ्य विभाग को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। पूर्व एएनएम एवं जनकपुर निवासी 62 वर्षीय विधवा महिला ममता सिंह ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ। अविनाश खरे और विभाग के एक कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए जनकपुर थाना में शिकायत दी है। शिकायत में उन्होंने रिश्वत मांगने, फोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। ममता सिंह का कहना है कि वर्ष 2016 में सेवा समाप्त होने के बाद वे अपने कार्यकाल के दौरान देय जीपीएफ, जीआईएस और अन्य कटौती की राशि के भुगतान के लिए लगातार विभाग के चक्कर लगा रही हैं। उनका आरोप है कि भुगतान कराने के एवज में उनसे 50 हजार रुपये की मांग की गई। राशि देने में असमर्थता जताने पर उन्हें लगातार टालमटोल किया गया। शिकायत के अनुसार, 16 जुलाई 2026 को भुगतान की जानकारी लेने के लिए फोन करने पर विभागीय कर्मचारी ने पहले अभद्र व्यवहार किया और बाद में सीएमएचओ से बात कराने पर उन्होंने भी कथित रूप से अपमानजनक एवं अश्लील शब्दों का प्रयोग किया। ममता सिंह ने कहा कि वे 62 वर्षीय विधवा हैं और हृदय, किडनी, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। इस घटना से उन्हें मानसिक आघात पहुंचा है। उन्होंने दोनों आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर न्याय दिलाने की मांग की है। हालांकि, इस पूरे मामले में सीएमएचओ डॉ। अविनाश खरे ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि ममता सिंह की सेवाएं वर्ष 2016 में न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग-2) एवं 314 के तहत दोषसिद्ध होने के बाद नियमानुसार समाप्त की गई थीं।

नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे से हटाए जाएंगे घुमंतू पशु



कोरिया। जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने घुमंतू एवं बेसहारा मवेशियों के सुरक्षित विस्थापन के लिए व्यापक अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। सोमवार को कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने जिले के सभी ग्रामीणों, पशुपालकों और आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने मवेशियों को सड़कों, चौक-चौराहों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर खुला न छोड़ें। उन्होंने कहा कि सड़कों पर विचरण करने वाले मवेशी लगातार दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं, जिससे न केवल लोगों की जान जोखिम में पड़ती है बल्कि पशुधन की भी क्षति होती है। कलेक्टर ने कहा कि हर पशुपालक का दायित्व है कि वह अपने मवेशियों की उचित देखभाल करे और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखे। यह केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक कर्तव्य भी है। उन्होंने आम लोगों से भी इस जनहितकारी अभियान में सक्रिय सहयोग करने की अपील की, ताकि जिले में सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात व्यवस्था स्थापित की जा सके। उन्होंने बताया कि 16 जुलाई को आयोजित जिला स्तरीय गौधाम समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुरूप राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों सहित जिले की प्रमुख सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों को सुरक्षित गौधामों तक पहुंचाने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है। इस अभियान में जनपद पंचायतों, नगरीय निकायों, पशुधन विकास विभाग, राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग प्राधिकरण तथा राजस्व विभाग को समन्वित रूप से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।

बदलते बस्तर की नई उड़ान, कारली की बेटियों ने नीट यूजी में रचा इतिहास



दंतेवाड़ा। कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में पहचान रखने वाला बस्तर अब शिक्षा के क्षेत्र में नई इबारत लिख रहा है। जिले के अंतिम छोर तक पहुंची गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सकारात्मक परिणाम अब राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी दिख रहा है। इसका ताजा उदाहरण छू लो आसमान कन्या आवासीय कोचिंग सेंटर, कारली की छात्राओं ने पेश किया है। यदि बात पूरे जिले की करें तो कुल 22 छात्रों ने नीट एग्जाम में सफलता हासिल की है। साल 2026 की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट-यूजी में संस्था की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न केवल अपने परिवार और विद्यालय, बल्कि पूरे दंतेवाड़ा जिले का नाम रोशन किया है। छात्राओं की इस सफलता से जिले में खुशी का माहौल है। ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों से आने वाली इन बेटियों ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के दम पर यह साबित कर दिया कि अवसर मिलने पर प्रतिभा किसी भी क्षेत्र में परचम लहरा सकती है। संस्था की छात्रा दीपा मरकाम (पिताङ्क जोगाराम) ने 412 अंक हासिल कर सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वहीं नेहा नायक (पिता- वीर कुमार नायक) ने 388 अंक, उर्वशी ठाकुर (पिता- नरेंद्र कुमार ठाकुर) ने 375 अंक, तनिषा दास (पिता- रामस्वामी दास) ने 355 अंक, वासनी कोवाशी (पिता- मनकू राम) ने 345 अंक, दिव्यांजलि मोडियामी (पिता- किश्टैया मोडियामी) ने 317 अंक, पारो मरकाम (पिता- केशव मरकाम) ने 312 अंक, प्रार्थना सोरी (पिता- रामदेव सोरी) ने 310 अंक, रानू कुंजाम (पिताङ्क दिनेश कुंजाम) ने 308 अंक तथा रिंकी नाग (पिताङ्क पोदिया) ने 300 अंक प्राप्त कर सफलता अर्जित की। इन छात्राओं को अब काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रदेश के शासकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुर्वेद एवं पशु चिकित्सा जैसे प्रतिष्ठित पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने का अवसर मिलेगा। छात्राओं की इस उपलब्धि पर कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने सभी सफल छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि यह सफलता दंतेवाड़ा जिले में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे सकारात्मक बदलाव का प्रमाण है। जिले की बेटियां अब राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं, जो पूरे जिले के लिए गर्व की बात है।

अंतरजातीय विवाह के बाद वकील दंपती एसपी कार्यालय पहुंचे, समाज द्वारा बाहर करने का आरोप



खैरागढ़। कानून की किताबों में लोगों को उनके अधिकार बताने वाला एक वकील दंपती अब खुद अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने पुलिस के दरवाजे तक पहुंचा है। खैरागढ़ विकासखंड के ग्राम देवरी में अंतरजातीय विवाह को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पुलिस तक पहुंच गया है। अधिवक्ता नेमीचंद वर्मा और उनकी पत्नी प्रमिला सोनकर ने समाज के कुछ कथित पदाधिकारियों पर सामाजिक बहिष्कार, 35 हजार रुपये की अवैध वसूली, जबरन सामूहिक भोज कराने और मानसिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक खैरागढ़ को सौंपे गए आवेदन में नेमीचंद वर्मा ने बताया है कि उन्होंने सितंबर 2025 में अपनी इच्छा से प्रमिला सोनकर से विधिसम्मत विवाह किया। विवाह के कुछ समय बाद गांव में समाज की बैठक बुलाई गई, जिसमें कथित तौर पर यह फैसला सुनाया गया कि अंतरजातीय विवाह करने के कारण उनके परिवार पर 35 हजार रुपये का सामाजिक जुर्माना लगाया जाता है। शिकायत के मुताबिक उस समय उनके पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी। बाद में परिवार ने समाज के दबाव में यह राशि जमा कर दी, लेकिन इसके बाद भी मामला खत्म नहीं हुआ। आरोप है कि उनसे पूरे समाज के लिए सामूहिक भोज कराने और समाज की आराध्य वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा के समक्ष पूजा-अर्चना करने के लिए भी कहा गया। सामाजिक बहिष्कार खत्म होने की उम्मीद में परिवार ने यह सब भी किया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें और उनकी पत्नी को समाज में दोबारा शामिल नहीं किया गया। आवेदन में दावा किया गया है कि समाज के लोगों को यह निर्देश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति उनसे संबंध न रखे, उनके घर न जाए, उन्हें शादी-ब्याह, धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक बैठकों या अन्य आयोजनों में न बुलाया जाए। यहां तक कि समाज का कोई भी व्यक्ति उनके परिवार का कोई काम न करे। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस वजह से वे लंबे समय से सामाजिक अपमान, मानसिक तनाव और अलगाव का सामना कर रहे हैं। मामले को और गंभीर बताते हुए अधिवक्ता ने अपने आवेदन में लिखा है कि उनके पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। उनका दावा है कि इस रिकॉर्डिंग में समाज के एक सदस्य के साथ हुई बातचीत में सामाजिक बहिष्कार, 35 हजार रुपये की वसूली और समाज के निर्णय का जिक्र है। उन्होंने पुलिस को यह रिकॉर्डिंग और संबंधित मोबाइल जांच के लिए उपलब्ध कराने की सहमति भी दी है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

नवनामांकित अधिवक्ताओं को 20 हजार रुपए अनुदान दें: एचसी

बिलासपुर। हाईकोर्ट में नवनामांकित अधिवक्ताओं को मानदेय देने के मुद्दे पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने एकमुश्त 20 हजार रुपए अनुदान देने की प्रस्तावित योजना पर राज्य सरकार से निर्णय प्रक्रिया में तेजी लाने की अपेक्षा जताई है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा, न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ के समक्ष राज्य शासन की ओर से प्रस्तुत शपथपत्र में बताया गया कि 2 मार्च 2026 की बैठक के एजेंडा आइटम क्रमांक-6 के तहत छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल में नए पंजीकृत अधिवक्ताओं को उनकी प्रारंभिक आवश्यकताओं- जैसे कानून की पुस्तकें (लाइब्रेरी), टेबल और कुर्सी खरीदने के लिए एकमुश्त 20 हजार अनुदान देने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था।शासन ने बताया कि वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव को राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) के समक्ष रखने की सलाह दी है। इसके पहले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों में लागू समान योजनाओं एवं नियमों संबंधित राज्यों की जानकारी मांगी गई है। जानकारी प्राप्त होने के बाद प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

4 गुना रिटर्न का झांसा देकर की लाखों की ठगी

दुर्ग। दुर्ग जिले से ट्रेडिंग कंपनी में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया है। मामले में आरोपी तृप्ती साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक, आरोपी तृप्ती लोगों के बीच खुद को रैंबो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी का लीडर बताती थी। इस कंपनी में निवेश के जरिए 28 माह में चार गुना लाभ दिलाने का झांसा देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाती थी। साथ ही हर महीने 10 से 12 प्रतिशत रिटर्न देने का फर्जी दावा किया जाता था। उतई थाना में जोरतराई निवासी दीपक कुमार अहिरवार ने महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया। शिकायत में बताया गया है कि आरोपी तृप्ती साहू ने अपने परिचित ललित के उतई स्थित घर पर रैम्बो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी में निवेश करने का झांसा दिया। उसने दावा किया कि 28 माह में निवेश की गई राशि चार गुना हो जाएगी और हर महीने 10 से 12 प्रतिशत ट्रेडिंग रिटर्न मिलेगा। भरोसा दिलाने के लिए शुरुआत में पीड़ित से 5 लाख रुपये निवेश कराए और उस पर 45 हजार रुपये का लाभ भी दिया।

8 थाना प्रभारियों का तबादला, एसपी ने जारी किया आदेश

धमतरी। धमतरी जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाने की दिशा में पुलिस अधीक्षक (भा.पु.से.) ने 8 निरीक्षकों के स्थानांतरण और नवीन पदस्थापना का आदेश जारी किया हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। डेमोग्राफ़िक्स निरीक्षक शरद ताम्रकार को रक्षित केंद्र धमतरी से थाना प्रभारी अर्जुनी नियुक्त किया गया है। निरीक्षक अरुण साहू को थाना प्रभारी नगरी से थाना प्रभारी भखारा पदस्थ किया गया है। निरीक्षक उमेश पाटिल को रक्षित केंद्र धमतरी से थाना प्रभारी सिहावा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निरीक्षक समीर तिवारी को रक्षित केंद्र धमतरी से चौकी प्रभारी बिरेझर नियुक्त किया गया है। निरीक्षक सन्नी दुबे को रक्षित केंद्र धमतरी से थाना प्रभारी रुद्री पदस्थ किया है। निरीक्षक तापेश्वर नेताम को थाना प्रभारी भखारा से थाना प्रभारी नगरी की जिम्मेदारी दी गई है। निरीक्षक मधुनाथ ध्रुव को रक्षित केंद्र धमतरी से थाना प्रभारी बोराई नियुक्त किया गया है। निरीक्षक चन्द्रकांत साहू को थाना प्रभारी अर्जुनी से थाना प्रभारी साइबर पदस्थ किया गया है।

बेटे ने अपने ही पिता के आधार कार्ड में किया फर्जीवाड़ा

सूरजपुर। सुरजपुर जिले से धोखाधड़ी का हैरतअंगेज मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने अपने पिता के आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर न्यायालय को धोखा देने का प्रयास किया और इसी के दम पर उसने अन्य मामलों के आरोपियों की जमानत भी कराई। हालांकि मामले में आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल, कोतवाली पुलिस ने जयनगर थाना क्षेत्र के अजबनगर गांव के रंगपारा निवासी 34 वर्षिय देव प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जिसके उपर आरोप है कि उसने अपने पिता के आधार कार्ड से छेड़छाड़ किया गया है। आरोपी ने पिता के आधार कार्ड में अपना नाम दर्ज कराकर कुछ मामलों में न्यायालय के समक्ष पेश होकर उस फर्जी आधार कार्ड के जरिए पिता की जगह अपना हस्ताक्षर कर अन्य मामलों के आरोपियों की जमानत कराई गई है। वही आरोपी को जांच के लिए बार-बार बुलाए जाने पर वह जांच से भागता रहा, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले का खुलासा हो गया।

3,848 निवेशकों से 40.78 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी

रायगढ़। फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान 'ऑपरेशन क्लीन हंट' के तहत रायगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोतवाली पुलिस ने बहुचर्चित सहारा इंडिया निवेश धोखाधड़ी मामले में करीब तीन वर्षों से फरार चल रहे ब्रांच मैनेजर विजय कुमार शराफ (54) को कोतरारोड़ क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आरोपी को 20 जुलाई 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक, मामले में शिकायतकर्ता विकास निगानिया ने 29 सितंबर 2022 को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सहारा इंडिया के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कंपनी की विश्वसनीयता तथा आरबीआई से अधिकृत होने का भरोसा दिलाकर वर्ष 2017 के दौरान शिकायतकर्ता, उनकी माता और पत्नी से विभिन्न योजनाओं में करीब 40 लाख रुपये निवेश कराए। परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद भी निवेश की रकम वापस नहीं की गई।

प्रशासनिक अकर्मण्यता की निशानी बना टंकी

भरी बरसात में झरिया के जरिए ग्रामीण बुझा रहे हैं प्यास



मोहला-मानपुर। जल जीवन मिशन के जरिए हर घर को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के दावों के बीच मोहला-मानपुर जिले में एक ऐसा गांव भी है, जहां जल जीवन मिशन के तहत बना टंकी टॉवर बिना किसी काम के बुत बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण भरी बरसात में नदी में झरिया बनाकर अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं। ये गांव है मानपुर विकासखंड का पिट्टेमेटा! कभी नक्सलियों का गढ़ रहे इस महाराष्ट्र सीमावर्ती गांव के बाशिंदों को नक्सलवाद से मुक्ति तो मिल गई, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता और अनदेखी के चलते उपजा अभागापन आज भी इनका पीछा नहीं छोड़ रहा। यही वजह है कि एक ओर जहां बारिश में लोग तर-बतर हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस गांव के बाशिंदे पीने के पानी के लिए जद्दोजहद करने को मजबूर हैं। दरअसल, गांव में जल जीवन मिशन का पेयजल आपूर्ति कार्य पिछले करीब दो साल से अधूरा है। न तो घर-घर तक पाइप लाइन के जरिए पेयजल पहुंचाने का काम पूरा हो सका है, और न ही पाइप लाइन का बेहतर विस्तार हो पाया है। जल जीवन मिशन के नाम पर केवल पानी टंकी से युक्त टावर खड़ा कर दिया गया है, जो निर्माण के बाद कुछ समय तक घर-घर तो न सही। अलबत्ता टावर के नीचे टावर में लगे पाइप के जरिए पानी देकर ग्रामीणों के पेयजल का आधार जरूर बना रहा। लेकिन पाइप लाइन विस्तार के नाम पर जो पाइप लाइने गांव में जमीन खोदकर बिछाई गई। वो पाइप लाइन कुछ ही समय में जगह-जगह लीकेज हो गया, जिससे टंकी में सूखा पड़ा हुआ है। गांव में जल जीवन मिशन के तहत पूर्व से सोलर सिस्टम वाली एक छोटी सी टंकी वाली वर्षों पुरानी लाचार पेयजल व्यवस्था जरूर है, लेकिन उक्त टंकी में भी न तो पानी का पर्याप्त भंडारण हो पाता है।

केंद्रीय विद्यालय ग्रुप केंद्र सीआरपीएफ आरंग के नवीन भवन का उद्घाटन



आरंग। राष्ट्र निर्माण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में केंद्रीय विद्यालय, ग्रुप केंद्र, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आरंग के नवीन भवन का उद्घाटन समारोह उत्साह और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह में शिक्षा, अनुशासन, संस्कार और उत्कृष्टता के नए अध्याय की शुरुआत हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के मध्य अंचल के विशेष महानिदेशक दीपक कुमार रहे। वहीं छत्तीसगढ़ सेक्टर के महानिरीक्षक शालिन विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रुप केंद्र रायपुर के उपमहानिरीक्षक अजय कुमार सिंह ने की। उन्होंने अतिथियों का आत्मीय स्वागत करते हुए विद्यालय की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। समारोह का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत और पौधों के भेंट के साथ हुआ। स्वागत संबोधन में अजय कुमार सिंह ने केंद्रीय विद्यालय संगठन की पृष्ठभूमि और विद्यालय के विजन-मिशन पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर 1963 को 20 रेजिमेंटल स्कूलों से शुरू हुआ केंद्रीय विद्यालय संगठन आज 1331 से अधिक विद्यालयों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण, मूल्यपरक और समावेशी शिक्षा प्रदान कर रहा है।वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय आरंग में बालवाटिका-1 से 3 तथा कक्षा 1 से 5 तक कुल आठ कक्षाओं में करीब 320 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विद्यालय के लिए ग्रुप केंद्र सीआरपीएफ आरंग द्वारा अस्थायी भवन, पेयजल, शौचालय और खेल मैदान सहित आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वहीं नवीन स्थायी भवन के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया भी जारी है। खेलसमारोह के दौरान विद्यार्थियों ने भारतीय संस्कृति, कला और राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम का मंच संचालन केंद्रीय विद्यालय आरंग के शिक्षक प्रताप सोनी और लता गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। विद्यालय के प्राचार्य संजय कंसल ने अपने संबोधन में केंद्रीय विद्यालय संगठन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए ग्रुप केंद्र सीआरपीएफ के निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल को प्रमुख लोकायुक्त उबोवेजा ने आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन सौंपा

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से मंगलवार को



यहां लोकभवन में प्रमुख लोकायुक्त इंदर सिंह उबोवेजा ने भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को छत्तीसगढ़ लोक आयोग के गतिविधियों की जानकारी दी और आयोग का वर्ष 2025-26 का वार्षिक प्रतिवेदन सौंपा। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ लोक आयोग के सचिव दीपक अग्रवाल, उप सचिव सुश्री चित्रलेखा सोनवानी, कानूनी सलाहकार अजीत कुमार राजभानु एवं आयोग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

शिक्षा विभाग में सहायक ग्रेड-1 से भृत्य तक के कर्मचारियों का तबादला

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में प्रशासनिक आधार पर कर्मचारियों के तबादले किए हैं। विभाग द्वारा जारी अलग-अलग आदेशों के तहत सहायक ग्रेड-1, सहायक ग्रेड-2, सहायक ग्रेड-3 और भृत्य वर्ग के कर्मचारियों को नई पदस्थापना दी गई है। सभी स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे। जारी आदेशों में विनीत डेविड (सहायक ग्रेड-1), उर्मिला त्रिपाठी, ऋतुराज कौशिक, अविनाश चंद्राकर, तोषण दास माणिकपुरी, घनश्याम पटेल, कमलेश कुमार साहू, तोमन लाल माहले, नीलकंठ साहू, रामायण लाल सेन, नेहा गंगवार, वासुदेव बंजारे तथा चाणक्य विश्वकर्मा (भृत्य) सहित अन्य कर्मचारियों के नाम शामिल हैं, जिन्हें नई पदस्थापना दी गई है। आदेश के अनुसार संबंधित कर्मचारियों को तत्काल नई पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ता एसईसीआर 2025-26 में बचाया 65 लाख लीटर डीजल

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे



(एसईसीआर) ऊर्जा बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। स्वच्छ्रक्र ने अत्याधुनिक हेड ऑन जनरेशन प्रणाली को अपनाकर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 65 लाख लीटर से अधिक डीजल की बचत की है। इस बचत से रेलवे को लगभग 81 करोड़ की राजस्व बचत हुई है। वहीं तकनीक से 16,614 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भी कमी दर्ज की गई। इस पहल से रेल परिवहन में जहां नई उपलब्धि हासिल हुई वहीं ग्रीन एनर्जी की ओर से भी रेलवे ने कदम बढ़ा दिया है। एसईसीआर की 25 एलएचबी आधारित ट्रेनों में एचओजी (हेड ऑन जनरेशन) प्रणाली लागू होने के बाद, अब इन ट्रेनों के कोचों में रोशनी और एयर कंडीशनिंग के लिए जरुरी बिजली आपूर्ति डीजल जनरेटर के स्थान पर सीधे ओवरहेड उपकरण (ओएचई) के माध्यम से मिल रही है। इससे डीजल आधारित एंड ऑन जनरेशन (ईओजी) प्रणाली पर रेलवे की निर्भरता लगभग समाप्त हो गई है। इसके पहले एलएचबी ट्रेनों के दोनों सिरों पर लगे पावर कारों में लगे डीजल जनरेटर सेट कोचों को बिजली सप्लाई करते थे। एचओजी प्रणाली लागू होने के बाद यह व्यवस्था समाप्त होकर विद्युत इंजन से सीधे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। जिससे ईंधन की बचत के साथ परिचालन अधिक किफायती, सुरक्षित एवं पर्यावरण-अनुकूल बन गया है।

लंबित परीक्षा शुल्क रिफंड वाले अभ्यर्थियों के लिए व्यापमं ने जारी किया नया लिंक

रायपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ने परीक्षा शुल्क रिफंड का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। जिन उम्मीदवारों की फीस तकनीकी कारणों से वापस नहीं हो सकी थी, उनके लिए प्रोफाइल में नया ऑनलाइन लिंक उपलब्ध कराया गया है। इस लिंक के माध्यम से अभ्यर्थी अपने बैंक खाते की सही जानकारी अपडेट कर सकते हैं। बैंक विवरण का सत्यापन होने के बाद लंबित रिफंड राशि संबंधित खाते में भेजी जाएगी। मंडल ने अभ्यर्थियों से जल्द से जल्द अपनी जानकारी अपडेट करने की अपील की है। मंडल की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से लिया जाता है और रिफंड भी उसी प्रक्रिया से किया जाता है। हालांकि, कई अभ्यर्थियों के मामलों में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की समय-सीमा समाप्त होने या बैंक संबंधी तकनीकी कारणों के चलते राशि उनके खातों तक नहीं पहुंच पाई। इसी समस्या को दूर करने के लिए अभ्यर्थियों के प्रोफाइल में बैंक विवरण अपडेट करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। जिन अभ्यर्थियों को अभी तक आवेदन शुल्क वापस नहीं मिला है, वे सीजी व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर अपने प्रोफाइल में उपलब्ध नए लिंक का उपयोग कर सकते हैं। यहां उन्हें अपना बैंक खाता नंबर, आईएफएससी कोड और अन्य आवश्यक जानकारियां सही-सही दर्ज करनी होंगी। मंडल का कहना है कि बैंक विवरण का सत्यापन होने के बाद संबंधित खाते में रिफंड राशि भेज दी जाएगी। सीजी व्यापम ने अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी है कि यदि उन्होंने आवेदन किसी साइबर कैफे के माध्यम से किया है और भुगतान कैफे संचालक के बैंक खाते या यूपीआई से किया गया है, तो रिफंड की राशि भी उसी खाते में ट्रांसफर हो सकती है।

साय सरकार का डिजिटल नवाचार

ऋण योजना से राज्य के शासकीय कर्मचारियों के जीवन में जागी नई उम्मीद

१रायपुर। छत्तीसगढ़ की प्रगति में एक ऐसा अध्याय जुड़ गया है, जो प्रशासनिक सुधार के साथ ही राज्य के लाखों शासकीय कर्मचारियों के जीवन में नई उम्मीद और सुरक्षा का संचार भी कर रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा प्रारंभ की गई 'वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना' सुशासन की दिशा में एक महवपूर्ण कदम है। कर्मचारी कल्याण को केंद्र में रखकर तैयार की गई यह योजना एक वित्तीय सुविधा, संवेदनशील शासन, आधुनिक तकनीक और मानवीय दृष्टिकोण का संगम है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया है कि शासकीय सेवक राज्य के विकास के मूल में हैं। राज्य के मुखिया का मानना है कि जब कर्मचारी मानसिक और आर्थिक रूप से सशक्त होंगे तभी वह शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंच पाएंगे। यही सोच इस योजना की आत्मा है।

आज के दौर में स्वास्थ्य संबंधी, पारिवारिक आवश्यकता या अन्य आपात स्थिति जैसी आकस्मिक परिस्थितियां किसी भी कर्मचारी को आर्थिक संकट में डाल सकती हैं। ऐसे विपरीत समय में उनको निजी साहूकारों या ऊँचे ब्याज दर वाले ऋण विकल्पों का सहारा लेना पड़ता है जिससे वे और अधिक मानसिक दबाव वाली परिस्थिति में आ जाते हैं।



सीएम साय की 'वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना' कर्मचारियों की आर्थिक समस्या का सीधा और सटीक समाधान प्रस्तुत करती है। बिना ब्याज, त्वरित और सम्मानजनक आर्थिक सहायता, डिजिटल क्रांति का सशक्त उदाहरण बन रहा है। ई-कोष प्रणाली की सबसे बड़ी शक्ति है इसका पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी स्वरूप का होना। ई-कोष प्रणाली के माध्यम से इस योजना को लागू किया गया है इस सुविधा में कर्मचारी घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं।

इस योजना के तहत कर्मचारियों के द्वारा लिए गए ऋण पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं आता। आवेदन की पूरी प्रक्रिया पेपरलेस है जिसमें न फाइलों का झंझट है और न ही कार्यालय के चक्कर। इस योजना के लिए ई-केवाईसी आधारित सत्यापन एक तेज और सुरक्षित प्रक्रिया है। पारदर्शिता और समय की बचत के साथ भुगतान हितग्राहियों के बैंक खाते में सीधा पहुँचाया जा रहा है। प्राप्त ऋण का वेतन से आसानी से पुनर्भुगतान करने के लिए स्वचालित किस्त कटौती का प्रावधान है। यह पूरी प्रक्रिया समय बचाने के साथ भ्रष्टाचार और अनावश्यक देरी जैसी समस्याओं को भी समाप्त कर रही है। डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को साकार करने में यह योजना एक और सशक्त कदम साबित हो रहा है।

किसी भी योजना की सफलता उसके प्रभाव और उसकी स्वीकृति से मापी जाती है और इस योजना ने तो अपने प्रारंभिक चरण में ही उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इस योजना में अब तक 73 हज़ार से भी अधिक कर्मचारियों ने पंजीकरण कराया है जिसमें से लगभग 27 हज़ार कर्मचारियों ने योजना से लाभ प्राप्त किया है। प्रस्तुत आँकड़ा इस बात का भी प्रमाण हैं कि इसके माध्यम से प्रशासन और कर्मचारियों के बीच भरोसा और अपनापन स्थापित हुआ है। यह सरकारी पहल आज एक भरोसेमंद सहारा बन चुकी है।

साय सरकार के संवेदनशील और दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता को दर्शाने वाली यह पहल सुनिश्चित कर रही है कि राज्य के कर्मचारी महज़ कार्यबल ही नही बल्कि सम्मानित भागीदार भी हैं। राज्य के मुखिया ने यह भी कहा कि ऋण योजना आर्थिक सहायता के अलावा कर्मचारियों को मानसिक शांति भी देगी। जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास होता है कि संकट के समय सरकार उसके साथ खड़ी है तो उसका आत्मबल स्वत: बढ़ जाता है।

इस योजना की एक सबसे विशेषता यह है कि यह प्रदेश सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार डाले बिना संचालित की जा रही है। वित्त विभाग द्वारा तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रिया में डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित की गई है। डिजिटल प्रमाणीकरण के उच्च मानकों का पालन किया जा रहा है जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी गई है। कार्यप्रणाली का यह संतुलन दर्शाता है कि सरकार अपनी योजनाओं को टिकाऊ और प्रभावी बना रही है।

प्रदेश के वित्त मंत्री ने भी इस पहल को प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक शानदार कदम बताया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में बेहतर क्रेडिट स्कोर वाले कर्मचारियों को अधिक राशि के ऋण की सुविधा भी दी जा सकती है। इस योजना के लिए प्रदेश के कर्मचारी-अधिकारी संघ के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है क्योंकि इससे सरकार और कर्मचारियों के बीच विश्वास रिश्ता और भी मजबूत हो रहा है।

यह योजना वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के अलावा भविष्य की दिशा भी तय कर रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, पारदर्शिता और कर्मचारी कल्याण ने मिलकर, आधुनिक, उत्तरदायी और जनहितैषी प्रशासन की नींव रखी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का यह प्रयास छत्तीसगढ़ को विकसित और सशक्त राज्य बनने की दिशा में अग्रसर कर रहा है।

इस योजना की सफलता के साथ अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बनने जा रहा है छत्तीसगढ़। 'वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना' एक सरकारी योजना होने के अलावा कर्मचारी के सम्मान, सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाली एक सोच भी है। समग्रता से कहें तो यह योजना एक ऐसे भविष्य की झलक है जहां शासन और कर्मचारी मिलकर एक मजबूत, समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ निर्मित कर रहे हैं।

मुख्य सचिव ने सचिवों की ली उच्च स्तरीय बैठक

■ योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के समस्त विभागों के भार सादक सचिवों की बैठक ली। बैठक में विभागों के महत्वपूर्ण कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा है कि सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विभिन्न प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया दो वर्ष से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए है कि सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारियों की सूची विभागावार अद्यतन कर ली जाए।

मुख्य सचिव ने विभागीय सचिवों को उनके विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए है। बैठक में ई-ऑफिस, आधार बेस अटेंडेंस, लोक सेवा गारंटी, सूचना के अधिकार, सुघ्घर छत्तीसगढ़, नियद नेल्लानार योजना, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति, डी रेगुलेशन ई-गजट, सेवा सेतु, ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं, पीएम सूर्य घर बिजली सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की



प्रगति के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली गई। मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि आई-गॉट के तहत विभागवार चिन्हित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग की जाये। अधिकारी-कर्मचारियों को आई-गॉट के तहत विभाग की आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण दिलाने कहा है। मुख्य सचिव ने कहा है कि सभी विभागों की योजनाओं एवं सेवाओं को ऑनलाइन किया जाए।

बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, विधि एवं विधायी विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती सुषमा सावंत, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमख सचिव श्रीमती शहला निगार, मुख्यमंत्री एवं खनिज विभाग के सचिव श्री पी.दयानंद, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन, ऊर्जा विभाग के सचिव श्री सारांश मित्तर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री भीम सिंह, गृह विभाग के सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता, सामान्य प्रशासन एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, परिवहन विभाग के सचिव श्री एस.प्रकाश, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव सुश्री आर.शंगीता, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के सचिव श्री बसवराजु एस., राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव श्री भुवनेश यादव, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के संयुक्त सचिव श्री मयंक अग्रवाल सहित राज्य शासन के अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

उप मुख्यमंत्री साव व मंत्री रजवाड़े के पर्सनल स्टाफ में हुआ प्रशासनिक बदलाव

रायपुर। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने दो मंत्रियों की निजी स्थापना (पर्सनल स्टाफ) में महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने अलग-अलग आदेश जारी कर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और उप मुख्यमंत्री अरुण साव की टीम में नए अधिकारियों की पदस्थापना की है। इनमें एक नियुक्ति को विशेष प्रकरण मानते हुए पात्रता संबंधी शर्तों में भी छूट दी गई है, जिससे यह फैसला प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग में संयुक्त संचालक तथा वर्तमान में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सचिव के रूप में कार्यरत प्रतीक खरे की सेवाएं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की निजी स्थापना के लिए ली गई हैं। उन्हें अस्थायी रूप से विशेष सहायक के पद पर पदस्थ किया गया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, मंत्री कार्यालय के कामकाज को अधिक प्रभावी और समन्वित बनाने के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया है। प्रतीक खरे की नियुक्ति से जुड़ा आदेश इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि इसमें पात्रता संबंधी शर्तों को शिथिल करते हुए इसे विशेष प्रकरण के रूप में स्वीकृति दी गई है। सामान्य तौर पर निजी स्थापना में नियुक्तियों के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है, लेकिन इस मामले में विशेष अनुमति दिए जाने से प्रशासनिक हलकों में इसकी चर्चा हो रही है।



साय सरकार ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव के कार्यालय में भी नई पदस्थापना की है। जल संसाधन विभाग में कार्यरत सहायक अनुभाग अधिकारी भूपेन्द्र सिंह ध्रुव को उनकी निजी स्थापना में सहायक ग्रेड-3 के पद के विरुद्ध अस्थायी रूप से पदस्थ किया गया है। अरुण साव के पास लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी है। ऐसे में उनकी निजी स्थापना में किया गया यह बदलाव प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि मंत्रियों के निजी स्टाफ में अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति से विभागीय समन्वय, फाइलों के निपटारे और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है। विशेष रूप से बड़े विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे मंत्रियों के कार्यालयों में दक्ष अधिकारियों की तैनाती को प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर रेलवे अधिकारियों की बैठक

रायपुर। 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों के संबंध में मंगलवार को विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट श्री मयंक सोनी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में आयोजित की गई। इसमें रायपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी रेलवे पोस्ट प्रभारियों ने भाग लिया।



विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट मयंक सोनी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि रेलवे अधिनियम के अंतर्गत समझौतायोग्य प्रकरणों का अधिक से अधिक चिन्हांकन किया जाए और उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत में निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जाए। इससे अधिक से अधिक पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय का लाभ मिल सकेगा। बैठक में जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम के अंतर्गत संशोधित प्रावधानों की विस्तृत जानकारी भी दी गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पात्र प्रकरणों का समयबद्ध परीक्षण कर राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उनके अधिकतम निराकरण का प्रयास सुनिश्चित करें। सोनी ने सभी पोस्ट प्रभारियों से समन्वित एवं सक्रिय प्रयास करने का आह्वान किया, ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जा सके और आम नागरिकों को त्वरित, सुलभ एवं प्रभावी न्याय उपलब्ध कराया जा सके।

22 और 23 जुलाई को 8 मेमू और पैसेंजर ट्रेन कैंसिल

■ भाटापारा और हथबंध स्टेशनों के बीच तीसरी लाइन सेक्शन पर चलेगा काम

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में भाटापारा और हथबंध स्टेशनों के बीच तीसरी लाइन सेक्शन पर ऑटो सिग्नलिंग कमीशनिंग के लिए नॉन-इंटरलॉकिंग (एनआई) काम किया जाएगा। इसके चलते 22 और 23 जुलाई को बिलासपुर, रायपुर, कोरबा और गेवरा रोड रूट की 8 मेमू और पैसेंजर ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। जिससे यात्रियों की मुसीबतें बढ़ जाएंगी।

रेलवे प्रशासन का दावा है कि बिलासपुर रेलवे जोन में इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट का काम तेजी से चल रहा है। इस काम को जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। ताकि, इससे यात्रियों को सुविधाएं मिल सके। इस कड़ी में तीसरी लाइन का कार्य भी चल रहा है।

इसके तहत रायपुर मंडल के भाटापारा-हथबंध स्टेशनों के मध्य तीसरी लाइन सेक्शन में ऑटो सिग्नलिंग कमीशनिंग का काम किया जाएगा। इस कार्य के फलस्वरूप कुछ यात्री गाडियों का परिचालन प्रभावित रहेगा।

रद्द होने वाली गाड़ियां

22 जुलाई को गाड़ी संख्या 68728 रायपुर-बिलासपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी।

22 जुलाई को गाड़ी संख्या 68734 बिलासपुर-गेवरा रोड मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी।

22 जुलाई को गाड़ी संख्या 68733 गेवरा रोड-बिलासपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी।

22 जुलाई को गाड़ी संख्या 68719 बिलासपुर-रायपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी।

22 जुलाई को गाड़ी संख्या 58203 कोरबा-रायपुर पैसेंजर रद्द रहेगी।

22 जुलाई को गाड़ी संख्या 58204 रायपुर-कोरबा पैसेंजर रद्द रहेगी।

22 जुलाई को गाड़ी संख्या 68746 रायपुर- गेवरा रोड मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी।

23 जुलाई को गाड़ी संख्या 68745 कोरबा-रायपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी।

22 जुलाई को 68862/68861 झारसुगुड़ा-गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू बिलासपुर स्टेशन पर ही समाप्त और यहीं से प्रारंभ होगी। इस दौरान बिलासपुर-गोंदिया-बिलासपुर के बीच इसका संचालन रद्द रहेगा।

पूर्व कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया का भाजपा पर गंभीर आरोप, कहा-

पीएससी घोटाले के नाम पर फैलाया भ्रम

रायपुर। दिल्ली में छात्रों के आंदोलन पर चर्चा करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने भाजपा पर प्रदेश में पीएससी घोटाले के नाम पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। वहीं पेपर लीक पर कहा कि जहां से पेपर सेट हो रहे हैं, वहीं से पेपर लीक हो रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी के लोग पेपर सेट कर रहे हैं। मंत्री पेपर बेच रहे हैं।

पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार में मंत्री रहे शिव डहरिया ने पेपर लीक की वजह से मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जनरल डायर ने किसी को नहीं छोड़ा। धरना-प्रदर्शन करने वाले लोगों ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। हड़ताल केवल दिल्ली में नहीं, बल्कि पूरे देश भर में हो रही है। रायपुर भी छात्रों ने प्रदर्शन किया है। सरकार छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही है।

वहीं बिलासपुर और रायपुर में जलभराव को लेकर शिव डहरिया ने कहा कि नगरीय निकाय की



स्थिति खराब है। पहले कभी पानी नहीं भरता था। कहीं भी दिक्कत होती, तो तुरंत सुधार लिया जाता था। आज बड़े-बड़े मंत्री, केंद्रीय मंत्री और विधायक वहां से आते हैं। पूरे प्रदेश की न्यायधानी है, लेकिन आज वहां गाड़ियां डूब जा रही है, तो सरकार के लिए डूब मरने की स्थिति है।

उन्होंने कहा कि विधानसभा में गला फाड़-फाड़ के चिलाने से कुछ नहीं होगा। सरकार असंवेदनशील हो चुकी है। भ्रष्टाचार करने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। सब जगह रेट बंधे हुए हैं। ऐसी व्यवस्था है तो जनता के काम कैसे होगे।

वहीं दुर्ग में शिक्षामंत्री के बंगले के बाहर अतिथि शिक्षकों के प्रदर्शन पर पूर्व मंत्री ने कहा कि डीएड अभ्यर्थी पिछले कई महीनों से आंदोलन पर हैं। प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। साढ़े 10 हजार स्कूल बंद कर देने के बाद भी शिक्षक नहीं है। प्रदेश में शिक्षा का रैंकिंग निचले स्तर पर पहुंच गया है। अतिथि शिक्षक प्रजातांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ में हर वर्ग परेशान है, प्रदेश में अराजकता का माहौल है।

बीजेपी की बैठक पर पूर्व कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि भाजपा में इतनी गुटबाजी है कि मुख्यमंत्री काम करने में सक्षम नहीं है। मुख्यमंत्री रिमोट से चल रहे है। देश में कानून व्यवस्था लचर है, सबसे ज्यादा स्थिति खराब छत्तीसगढ़ में है। अविश्वास प्रस्ताव में किसी ने अच्छे से जवाब नहीं दिया। एक दिन गुटबाजी भाजपा को ले डूबेगी।

कार्यालय जिला बाल संरक्षण अधिकारी जिला राजनांदगांव

दावा-आपत्ति

1. बच्चे का नाम :- प्राची ठाकुर
2. बच्चे का प्राप्ति दिनांक :- 14/05/2026
3. संस्था :- स्नेह सर्वोदय सेवा संस्था बालगृह (बालिका) राजनांदगांव (छ.ग.)
4. रंग :- गोरी
5. उम्र :- 14 वर्ष 11 माह (लगभग)



उक्त बालक को दिनांक 14.05.2026 को बालक कल्याण समिति राजनांदगांव (छ.ग.) के आदेश कंमांक 198/ बा0क0स0/26-27 राजनांदगांव दिनांक 14.05.2026 से अस्थाई संरक्षण हेतु स्नेह सर्वोदय सेवा संस्था बालगृह (बालिका) राजनांदगांव (छ.ग.) में संरक्षण प्राप्त है। बालिका के वैधानिक पालक/अभिभावक होने का दावा अपत्ति दर्ज कराना चाहते है, तो प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस के भीतर जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास, संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन कक्ष क्रमांक 11 कलेक्ट्रेट परिसर जिला राजनांदगांव अथवा स्नेह सर्वोदय सेवा संस्था बालगृह (बालिका) राजनांदगांव (छ.ग.) मे दर्ज करा सकते हैं। उक्त समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावा-आपत्तियों पर विचार नही किया जायेगा तथा दत्तक ग्रहण की कार्यवाही की जायेगी।

यह विज्ञापन मेरे द्वारा जारी किया गया।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी
जिला बाल संरक्षण इकाई (मबावि)
जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

जी-262702264/3

मुस्लिम नेताओं के दिल्ली बैठक का एजेंडा क्या है?

अभिनय आकाश

दिल्ली की सियासत में इन दिनों दो अलग-अलग मोर्चों पर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के बैनर तले युवाओं और छात्रों का प्रदर्शन सड़क पर उग्र रूप ले रहा है और सरकार के खिलाफ तीखी नारेबाजी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अंदरखाने एक अलग ही राजनीतिक रणनीति तैयार की जा रही है। प्रमुख मुस्लिम नेताओं और धर्मगुरुओं की अगुवाई में एक ऐसा एजेंडा आकार ले रहा है, जिसकी गूंज आने वाले दिनों में देश की सियासत को गरमा सकती है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या एक तरफ छात्रों के आंदोलन और दूसरी तरफ इस नई गोलबंदी के बीच लोकतंत्र की आड़ में सरकार पर दबाव बनाने या कोई नया मोर्चा खोलने की तैयारी है? क्या यह सब महज संयोग है या लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सरकार पर चौतरफा दबाव बनाने की कोई बड़ी पटकथा? दरअसल इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स यानी आईएमसीआर नामक संगठन ने आगामी 24 जुलाई को दिल्ली में एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण बैठक का ऐलान कर दिया है। इस बैठक में मुस्लिम समुदाय की कई बड़ी और जानीमानी हस्तियों के छूटने की खबर है। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस मंच पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत कई राजनीतिक दलों के मुस्लिम सांसद एक साथ नजर आएंगे। यानी मंच बड़े लेवल पर सजाया जाएगा। इतना ही नहीं जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल अवार्ड जैसे प्रभावशाली संगठनों के नुमाइंदे भी इस चर्चा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। यह कोई आम सम्मेलन नहीं है बल्कि यह सम्मेलन इसलिए बुलाया गया है ताकि देश के मुसलमानों को लोकतंत्र के खिलाफ खड़ा किया जा सके। करोड़ों मुसलमानों को चुनाव के बहिष्कार के लिए उकसाया जा सके। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मुसलमानों के बड़े ठेकेदार रहनुमा इकट्ठा होकर क्या करने वाले हैं? क्या भारत के खिलाफ मोदी सरकार के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रचने की प्लानिंग हो रही है? दरअसल बैठक के आधिकारिक एजेंडे में मदरसे पर होने वाली प्रशासनिक कारवाई, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी और मुस्लिम समुदाय से जुड़े अन्य मुद्दे बुलडोजर एक्शन को शामिल किया गया है। लेकिन इस पूरे सम्मेलन में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है और जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है चुनाव का बहिष्कार। चुनाव का बहिष्कार। अब सवाल यह है कि कौन करने वाला है चुनाव का बहिष्कार? क्या मुस्लिम अब वोट नहीं डालेंगे? संगठन की ओर से यह संकेत दे दिए गए हैं कि इस बैठक में महात्मा गांधी के ऐतिहासिक असहयोग आंदोलन की तर्ज पर मुस्लिम समुदाय के जरिए चुनावी प्रक्रिया का पूरी तरह से बहिष्कार करने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। कभी सोचा है कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से सबसे ज्यादा तकलीफ किसे हो रही है? विपक्षी दलों को और उनसे भी ज्यादा मुसलमानों को, मौलानाओं को जिनकी दुकान पर हथौड़ा चल रहा है। वही बार-बार चिल्लाते हैं, बैठक बुलाते हैं, माहौल गरमाते हैं। किसी ना किसी बहन मुसलमानों को इकट्ठा कर सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश में लग जाते हैं। अब देखिए ना यह जो बैठक बुलाई जा रही है, इसमें क्या मुद्दे उठाए जा रहे हैं। गौर से सुनिए। मदरसों पर चल रहे बुलडोजर एक्शन। बुलडोजर एक्शन मजहब देखकर नहीं बल्कि अवैध चीजें देखकर किया जा रहा है। फिर चाहे उसकी जद में मस्जिद आए या फिर मंदिर आए। दस्तावेज है तो बच जाएंगे। नहीं है अवैध है तो जाहिर सी बात है बुलडोजर की जद में जाएंगे।

मानसून सत्र : लोकतंत्र का महायुद्ध या राष्ट्रीय सहमति का महापर्व ?

विनोद कुमार सिंह



भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी संसद है। संविधान निर्माताओं ने संसद को केवल कानून बनाने की संस्था नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संवाद, जनाकांक्षाओं की अभिव्यक्ति और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाले सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच के रूप में स्थापित किया। संसद की गरिमा केवल सत्ता पक्ष के बहुमत से नहीं,बल्कि एक सशक्त,जागरूक और उत्तरदायी विपक्ष से भी निर्मित होती है। लोकतंत्र का सौंदर्य इसी संतुलन में निहित है। सरकार जनादेश का प्रतिनिधित्व करती है,जबकि विपक्ष जनमत की निगरानी करता है। दोनों की सक्रिय और रचनात्मक भूमिका ही संसदीय लोकतंत्र को जीवंत बनाती है।इसी लोकतांत्रिक परंपरा को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से प्रत्येक संसदीय सत्र से पूर्व केन्द्र सरकार सर्वदलीय बैठक आयोजित करती है। यद्यपि यह संविधान द्वारा अनिवार्य नहीं है, फिर भी दशकों से विकसित यह संसदीय परम्परा सरकार और विपक्ष के बीच संवाद का सबसे महत्त्वपूर्ण माध्यम रही है।

इस बैठक में आगामी सत्र की कार्ययोजना,विधायी प्राथमिकताओं,जनहित से जुड़े मुद्दों तथा सदन को व्यवस्थित और सुचारु रूप से चलाने पर विचार-विमर्श किया जाता है। लोकतंत्र में संवाद की यह परम्परा ही राजनीतिक मतभेदों को संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर बनाए रखने का आधार बनती है। 20 जुलाई से प्रारम्भ हुए संसद के मानसून सत्र की शुरुआत इस बार सहमति के वातावरण में नहीं,बल्कि तीखे राजनीतिक मतभेदों के साथ हुई है। सत्र से पूर्व आयोजित सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी,तृणमूल कांग्रेस तथा इंडिया गठबंधन के कई दलों ने उन सांसदों को आमंत्रित किए जाने पर आपत्ति जताई,जिन्होंने अपनी मूल राजनीतिक पार्टी से अलग होने की घोषणा की है अथवा जिनकी स्थिति दल-बदल विरोधी कानून के अंतर्गत अभी लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष विचाराधीन है। विपक्ष ने इसे संसदीय मर्यादाओं के विपरीत बताते हुए बैठक का बहिष्कार किया।

सरकार का पक्ष है कि निमंत्रण संसदीय अभिलेखों और उपलब्ध आधिकारिक स्थिति के आधार पर भेजे गए हैं तथा इसमें किसी प्रकार की प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं हुआ है।यह विवाद केवल एक बैठक तक सीमित नहीं है।इसके पीछे भारतीय राजनीति में लगातार बढ़ता अविश्वास, दल -बदल की घटनाएँ, गठबंधनों का विघटन,राजनीतिक ध्रुवीकरण तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता को लेकर उठ रहे प्रश्न भी जुड़े हैं। विपक्ष का आरोप है कि सत्तारूढ़ दल विपक्ष को कमजोर करने की दीर्घकालिक राजनीतिक रणनीति पर कार्य कर रहा है।

सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहती है कि लोकतंत्र में प्रत्येक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को कानून के दायरे में राजनीतिक निर्णय लेने का अधिकार है तथा दल- बदल से जुड़े मामलों का अंतिम निर्णय संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुसार संबंधित अध्यक्ष अथवा सभापति ही करते हैं। इस बार मानसून सत्र का महत्त्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि सरकार अनेक महत्त्वपूर्ण विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करने अथवा पारित कराने की तैयारी में है।संसद की उपलब्ध कार्यसूची और सरकारी संकेतों के अनुसार आयकर(संशोधन) विधेयक, सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम विकास(संशोधन) विधेयक, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने संबंधी विधेयक, राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक तथा विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम में संशोधन जैसे विषय सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। हालाँकि संसद की कार्यसूची गतिशील होती है और कार्यमंत्रणा समिति अथवा सरकार के निर्णय के अनुसार इसमें परिवर्तन,नए विधेयकों का समावेश अथवा प्राथमिकताओं का पुनर्निर्धारण भी संभव है।सरकार का दावा है कि इन विधेयकों का उद्देश्य प्रशासनिक सुधार, न्यायिक दक्षता, कर व्यवस्था का सरलीकरण, निवेश को प्रोत्साहन, सुशासन तथा पारदर्शिता को और अधिक सुदृढ़ करना है।सरकार का यह भी कहना है कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए विधायी सुधारों की गति बनाए रखना समय की आवश्यकता है। यही कारण है कि मानसून सत्र को सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के सबसे महत्त्वपूर्ण विधायी सत्रों में से एक मान रही है। दूसरी ओर राजनीतिक विमर्श का सबसे संवेदनशील विषय संविधान संशोधन, परिसीमन तथा महिला आरक्षण का प्रभावी क्रियान्वयन बना हुआ है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद से पारित हो चुका है,किन्तु उसका वास्तविक क्रियान्वयन नई जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही संभव है। विपक्ष का आरोप है कि महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने के बजाय भविष्य की प्रक्रिया से जोड़ दिया गया है।

सरकार का कहना है कि संविधान के वर्तमान प्रावधानों के अंतर्गत परिसीमन के बिना आरक्षण लागू करना संभव नहीं है। स्पष्ट है कि यह विषय राजनीतिक बहस के साथ-साथ संवैधानिक व्याख्या का भी प्रश्न बन चुका है।परिसीमन आने वाले वर्षों की भारतीय राजनीति का सबसे महत्त्वपूर्ण संवैधानिक विषय बनता दिखाई दे रहा है। जनसंख्या के आधार पर लोकसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन से राज्यों के संसदीय प्रतिनिधित्व में परिवर्तन की संभावना है।दक्षिण भारत के अनेक राज्यों और क्षेत्रीय दलों ने पहले ही आशंका व्यक्त की है कि जनसंख्या नियंत्रण में सफलता प्राप्त करने वाले राज्यों को प्रतिनिधित्व के स्तर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है।दूसरी ओर उत्तर भारत के राज्य समान जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल देते हैं। इसलिए परिसीमन केवल चुनावी गणित का विषय नहीं, बल्कि संघीय ढाँचे,क्षेत्रीय संतुलन और राष्ट्रीय राजनीतिक संरचना से जुड़ा संवेदनशील प्रश्न बन गया है। मानसून सत्र में विपक्ष की रणनीति भी लगभग स्पष्ट दिखाई दे रही है। विपक्ष संसद के भीतर सरकार को भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी, महँगाई, कृषि संकट, राज्यों के अधिकार, संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता, जाँच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग, दल-बदल, सामाजिक न्याय तथा महिला आरक्षण के क्रियान्वयन जैसे विषयों पर घेरने की तैयारी में है। इसके अतिरिक्त लद्दाख को संवैधानिक संरक्षण,छठी अनुसूची के प्रावधानों तथा पर्यावरणीय संरक्षण की माँग को लेकर सोनम वांगचुक द्वारा चलाए गए आंदोलन को भी विपक्ष राष्ट्रीय विमर्श का विषय बनाने का प्रयास करेगा।सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास, पर्यावरणीय संतुलन और स्थानीय जनप्रतिनिधित्व अब केवल क्षेत्रीय मुद्दे नहीं,बल्कि राष्ट्रीय नीति के अभिन्न अंग बन चुके हैं। भ्रष्टाचार का प्रश्न भी इस सत्र में प्रमुखता से उठ सकता है।विपक्ष विभिन्न सरकारी निर्णयों, सार्वजनिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली तथा राजनीतिक जवाबदेही को लेकर सरकार से प्रश्न पूछने की तैयारी में है।वहीं सरकार डिजिटल भुगतान, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण,सरकारी खरीद की ई-प्रणाली, जीएसटी, डिजिटल प्रशासन तथा तकनीक आधारित पारदर्शिता को भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत कर रही है। स्वाभाविक है कि इस विषय पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद केवल बहुमत का मंच नहीं होती। संविधान के अनुच्छेद 107 से 111 तक विधेयकों की संसदीय प्रक्रिया का उल्लेख है,जबकि अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की विशेष प्रक्रिया निर्धारित करता है।इसी प्रकार दसवीं अनुसूची दल-बदल विरोधी कानून का आधार है। इन प्रावधानों का मूल उद्देश्य लोकतांत्रिक स्थिरता,जनादेश की रक्षा और संसदीय मर्यादाओं को सुरक्षित रखना है।यदि राजनीतिक विवादों का समाधान इन्हीं संवैधानिक व्यवस्थाओं के माध्यम से होता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है; किन्तु यदि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास बढ़ता है,तो उसका प्रभाव लोकतांत्रिक व्यवस्था पर दूरगामी होता है।यह भी स्मरण रखना होगा कि संसद का दायित्व केवल विधेयक पारित करना नहीं है। संसद सरकार से प्रश्न पूछती है,नीतियों की समीक्षा करती है,सार्वजनिक धन के उपयोग पर निगरानी रखती है तथा जनता की आकांक्षाओं को राष्ट्रीय नीति में स्थान देती है। इसलिए संसद का प्रत्येक दिन और प्रत्येक घंटा राष्ट्र की अमूल्य लोकतांत्रिक पूँजी है। यदि पूरा सत्र केवल हंगामे, नारेबाज़ी और स्थगन की भेंट चढ़ जाता है,तो सबसे बड़ा नुकसान जनता के विश्वास और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को होता है। आज भारत महँगाई, रोजगार, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं,कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, कृषि सुधार, राष्ट्रीय सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक समरसता जैसी अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन विषयों पर गंभीर संसदीय विमर्श की अपेक्षा केवल विपक्ष या सरकार की नहीं,बल्कि पूरे राष्ट्र की है। जनता चाहती है कि संसद राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का मंच अवश्य बने, किन्तु राष्ट्रीय समाधान का केन्द्र भी बनी रहे। 20 जुलाई से प्रारम्भ हुआ यह मानसून सत्र केवल सरकार के विधायी एजेंडे अथवा विपक्ष के राजनीतिक प्रतिरोध तक सीमित नहीं है।

पुराण दिग्दर्शन ....



विश्व विद्या-निरुपणाध्यायः (दशम अध्याय)

(गतांक से आगे...)

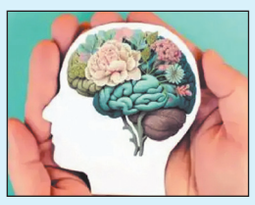
क्रमशः ...

ऋषिजनों की प्रतिभा पर चकित रहना पड़ता है। पृथ्वी का नाप, तोल, व्यास, परिधि, क्षेत्रफल और पार्थिव आकर्षण की सीमा,- तथा पृथ्वीस्थ समस्त पर्वतों की स्थिति, विस्तार उनकी चोटियों की ऊँचाई और पृथ्वी गर्भमें धंसी हुई गहराई, तत्सम्बद्ध धातुओं तथा रत्नों का व्यौरा, इसी प्रकार प्रसिद्ध नदियों, सरोवरों, नदों महारण्यों और तत्तत्कालीन वन उपवनों का संस्थान- एवं सामयिक सम्राटों द्वारा निर्धारित तत्तत् प्रदेशों की ह्रदबन्दी गर्ज है कि जो बातें आज उन्नत कहे जाने वाले जमाने में भी इदमित्थं नहीं जानी जा सकी हैं पुराणों में उन सब का सर्वाङ्गपूर्ण एवं यथार्थ वर्णन विद्यमान है। उदाहरण के लिये भूमि में धंसे हुये पर्वत पादों को ही लीजिये। वर्तमान अनुसन्धायक आज तक न इस रहस्य को जान सके हैं न भविष्य में जान सकेंगे ऐसी सम्भावना है, क्योंकि जरीब और फीतों को डाल कर नाप पैमाइत करने वाले जड़वादी मौजूदा अनुसन्धायक भूगर्भ में धंसने की योग्यता नहीं रखते ! यह रहस्य तो वे ही आत्मवादी महर्षि जान सकते हैं जो कि अष्टाङ्ग योग द्वारा - ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा। - के अनुसार समस्त ब्रह्माण्ड के परोक्ष पदाथों को भी हस्तामलक कर सकने की क्षमता रखते हों ! यह योग्यता केवल भारनीय ऋषियों की ही बपौती थी इसलिये आज साइन्स के प्रकाश में जो कुछ भी दीख पड़ता है वह पुराणवर्णात रहस्यों की धुंधलो छायामात्र है। पौराणिक भूगोल पर जितने आक्षेप किये जाया करते हैं हम उन सवको प्रायः तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं, यथा-

(1) अनुपलब्धि - अर्थात् पुराणों में जिन जिन नद नदी सरोवरों पर्वतों किंवा नगरों का होना प्रकट किया है, बहुत छानबीन करने पर भी अब कहीं वे चीजें प्राप्त नहीं होतीं। क्रमशः ...

विश्व मस्तिष्क दिवस

श्वेता पांडेय



ब्रेन हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ब्रेन हेल्दी रहना बेहद जरूरी है। आज के समय में सबसे अधिक ब्रेन यानी मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों से ग्रसित हैं। इसलिए हर साल 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को मस्तिष्क स्वास्थ्य के प्रति जागरूक का जा सके और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों को रोका जाए।

दरअसल विश्व मस्तिष्क दिवस की शुरुआत साल 2014 में विश्व न्यूरोलॉजी फेडरेशन (World Federation of Neurology – WFN) द्वारा किया गया था। 22 जुलाई 1957 को WFN की स्थापना बेल्जियम में हुई थी। जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के बारे में लोगों में जागरूकता और मस्तिष्क स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना है। तभी से हर साल 22 जुलाई को विश्व ब्रेन डे यानी कि विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। पहली बार विश्व ब्रेन डे 22 जुलाई 2014 को मनाया गया था। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर विश्व मस्तिष्क दिवस का महत्व क्या है तो आपको बता दें कि मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों और स्थितियों के प्रति लोगों को जाकरूक करना है। ताकि लोगों को मस्तिष्क स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जानकारी दिया जा सके और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के लक्षणों की पहचान करना और समय पर उपचार किया जा सके। क्योंकि आज भी लोग ब्रेन से संबंधित बीमारियों के प्रति बहुत कम जागरूक हैं जिसके कारण यह आगे चलकर एक गंभीर बीमारी का रूप ले लेती हैं। जिसमें हर साल लाखों की मौत सिर्फ ब्रेन से संबंधित रोगों के कारण होती है।

मस्तिष्क के लिए फायदेमंद आहार

● वसायुक्त मछलियां ओमेगा-3 फैटी एसिड का बेहतरीन स्रोत होती हैं, इसके सेवन से याददाश्त की समस्या ठीक होती है। ● पालक, सलाद, ब्रोकली जैसी पत्तेदार सब्जियां-साग मस्तिष्क के लिए बेहतरीन भोजन हैं। ● वसायुक्त मछलियों की तरह, नट्स और सीड्स में भी ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट का उच्च स्तर होता है, जो मस्तिष्क के लिए बहुत लाभकारी हैं। ● नट्स का नियमित सेवन उम्र से संबंधित स्मृति हानि के जोखिम को कम कर सकता है। ● बादाम, अखरोट, हेजलनट्स और सूरजमुखी के बीज आदि का सेवन आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। ● आहार में डार्क चॉकलेट को शामिल करने भी बढ़िया विकल्प है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जिससे मस्तिष्क की बीमारियों का जोखिम कम होता है।

मस्तिष्क के लिए हानिकारक चीजें

● मीठे पेय पदार्थ जैसे सोडा, स्पोर्ट्स ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक और पैक्ड फलों के जूस में चीनी की अधिकता होती है, जो मस्तिष्क के लिए नुकसादायक है। ● चूहों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि चीनी का अधिक सेवन मस्तिष्क में सूजन और याददाश्त से संबंधित दिक्कतें बढ़ा सकती है। ● मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए शराब से बिल्कुल दूरी बनाने की सलाह दी जाती है।

कैसे मजबूत हो रही है नई दिल्ली की अफ्रीका नीति?

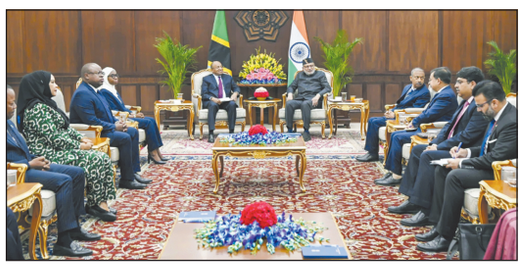
अरुणिम भूयान

राष्ट्रपति हुसैन अली म्विनयी की 17-20 जुलाई तक की भारत यात्रा, भारत और तंजानिया के अर्ध-स्वायत्त द्वीपसमूह जांजीबार के बीच एक सामान्य द्विपक्षीय जुड़ाव से कहीं बढ़कर थी। यह यात्रा अफ्रीका के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली के उस बड़े रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो पारंपरिक सहायता-आधारित कूटनीति के बजाय विकास साझेदारी, शिक्षा, डिजिटल बदलाव, समुद्री सहयोग और क्षमता निर्माण पर केंद्रित है।

इसके साथ ही, यह अफ्रीका महाद्वीप पर बढ़ते भू-राजनीतिक कॉम्पिटिशन के बीच, ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों) की एक प्रमुख आवाज के रूप में खुद को स्थापित करने के भारत के बढ़ते प्रयासों को भी रेखांकित करती है। उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन के आधिकारिक एक्स हैंडल पर किए गए एक पोस्ट के अनुसार, दोनों नेताओं ने रविवार को यहां राष्ट्रपति भवन में व्यापक और सार्थक चर्चा की।

उपराष्ट्रपति कार्यालय ने कहा, इस बैठक ने भारत-तंजानिया की स्थायी साझेदारी और जांजीबार के साथ भारत के विशेष संबंधों को फिर से मजबूत किया है, जो सदियों पुराने समुद्री, सांस्कृतिक और आपसी जन-संबंधों पर टिके हैं। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, विकास साझेदारी, पर्यटन, ब्लू इकोनॉमी (समुद्री अर्थव्यवस्था), शिक्षा, प्रौद्योगिकी और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।

इससे पहले दिन में, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी राष्ट्रपति म्विनयी के साथ एक बैठक की थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य में ज़ांज़ीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉ. हुसैन अली म्विनयी से आज दिल्ली में मिलकर बहुत खुशी हुई। हमने उच्च शिक्षा, क्षमता निर्माण, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, एआई, डिजिटल और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अपने सहयोग को



बढ़ाने पर चर्चा की।

हालांकि राष्ट्रपति म्विनयी तंजानिया की केंद्र सरकार के बजाय जांजीबार (अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र) का प्रतिनिधित्व करते हैं, फिर भी उनकी इस यात्रा का बहुत बड़ा राजनयिक महत्व था। ऐसा इसलिए है क्योंकि पश्चिमी हिंद महासागर में पूर्वी अफ्रीकी तट पर ज़ांज़ीबार एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान पर स्थित है। इतिहास में इसने भारत, पूर्वी अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप को जोड़ने वाले प्रमुख समुद्री द्वारों में से एक के रूप में काम किया है।

भारत ने जांजीबार के साथ सदियों पुराने सभ्यतागत, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध बनाए रखे हैं। भारतीय मूल के बड़े समुदाय जांजीबार की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देना जारी रखे हुए हैं, जबकि हिंद महासागर के पार हुए ऐतिहासिक व्यापार ने दोनों देशों के लोगों के बीच स्थायी संबंधों की नींव रखी।

राष्ट्रपति म्विनयी की उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन और विदेश मंत्री जयशंकर के साथ हुई बैठकों ने इस ऐतिहासिक साझेदारी को फिर से मजबूत किया है, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डिजिटल तकनीक, स्वास्थ्य सेवा, जल प्रबंधन, उच्च शिक्षा और क्षमता निर्माण जैसे सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान की है।

शायद इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू 17 जुलाई को आईआईटी मद्रास के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति म्विनयी की भागीदारी थी, जो अक्टूबर 2023 में स्थापित आईआईटी मद्रास जांजीबार परिसर की सफलता को उजागर करता है।

यह कैंपस रणनीतिक रूप से कई मायनों में पहला है। यह किसी भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का पहला विदेशी कैंपस है। यह केवल अंतरराष्ट्रीय छात्रों को भारत बुलाने के बजाय, दुनिया को उच्च गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा निर्यात करने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करता है। यह विदेश में विकास सहायता देने के बजाय वहां संस्थानों का निर्माण करने के भारत के बदलते रुख को दर्शाता है। इसके अलावा, यह सतत विकास की बुनियाद के रूप में मानव संसाधन विकास पर भारत के जोर को साबित करता है।

अन्य बड़ी ताकतों द्वारा वित्तपोषित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विपरीत, इस आईआईटी कैंपस का मुख्य ध्यान अफ्रीका के भीतर ही वहां की अपनी वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं को तैयार करना है। यह भारत के उस पुराने दर्शन के बिल्कुल अनुकूल है, जो मानता है कि केवल वित्तीय सहायता देने की तुलना में क्षमता निर्माण से कहीं अधिक टिकाऊ और मजबूत साझेदारियां बनती हैं। आईआईटी मद्रास जांजीबार कैंपस की यह पहल पूरे अफ्रीका में भारत के विकास सहयोग मॉडल का एक प्रमुख (फ्लैगशिप) उदाहरण बन गई है।

जांजीबार भारत की व्यापक पूर्वी अफ्रीका नीति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत के तंजानिया, केन्या, मोज़ाम्बिक, मॉरीशस, सेशेल्स और मेडागास्कर के साथ मजबूत संबंध हैं, और ये सभी पश्चिमी हिंद महासागर में रणनीतिक स्थानों पर स्थित हैं। ये देश भारत के विजन सागर (SAGAR - Security and Growth for All in the Region) और इसके विस्तारित महासागर (MAHASAGAR) ढांचे के तहत भारत की समुद्री सुरक्षा प्रणाली के केंद्र में हैं।

म्विनयी की यात्रा ने अफ्रीका के साथ भारत के जुड़ाव की विशिष्ट प्रकृति को भी उजागर किया। कई बड़ी ताकतों के विपरीत, जिनका जुड़ाव अक्सर मुख्य रूप से रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित होता है, भारत का दृष्टिकोण मांग-आधारित विकास सहायता, स्थानीय क्षमता निर्माण, सस्ती तकनीक, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा सहयोग, कौशल विकास, शिक्षा और बिना किसी राजनीतिक शर्तों के रियायती वित्तपोषण पर आधारित है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल तकनीकों, जलापूर्ति और स्वास्थ्य पर हुई चर्चाएं विकासात्मक समाधानों के भारत के बढ़ते निर्यात को दर्शाती हैं। जिन्हें घरेलू स्तर पर सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)- जिसमें डिजिटल पहचान (identity), डिजिटल भुगतान और ई-गवर्नेंस शामिल हैं- कम लागत वाले तकनीकी समाधान तलाशने वाले अफ्रीकी देशों के बीच लगातार रुचि का केंद्र बना हुआ है।

थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एसोसिएट फेलो समीर भट्टाचार्य के अनुसार, म्विनयी की यह यात्रा इसलिए भी समझदारी भरी है क्योंकि जब भारत ने एक बार वहां आईआईटी कैंपस स्थापित कर दिया है, तो इसके बाद वहां अस्पतालों जैसी अन्य संबंधित विकास योजनाएं भी हमेशा शुरू की जा सकती हैं। म्विनयी की यह यात्रा ग्लोबल साउथ की आवाज बनने के भारत के बड़े राजनयिक दृष्टिकोण में भी पूरी तरह फिट बैठती है।

साल 2023 में जी20 की अध्यक्षता संभालने के बाद से, भारत लगातार इस बात की वकालत करता रहा है कि विकासशील देशों को वैश्विक शासन में अधिक प्रतिनिधित्व, उचित जलवायु वित्तपोषण, तकनीक तक सस्ती पहुंच मिलनी चाहिए। इसके साथ ही उन्हें खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार का अधिकार भी मिलना चाहिए।

भारत द्वारा आयोजित वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट्स ने प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बैठकों से पहले विकासशील देशों के विचारों और दृष्टिकोणों को एक साथ लाने का प्रयास किया है।

आज का इतिहास

1905 टाफ़्ट-कत्सुरु गुप्त समझौता हुआ।
1933 विली पोस्ट, न्यूयॉर्क शहर के फ्लोयड बेनेट फील्डिन ब्रूकलिन में सात दिन, उन्नीस घंटे की उड़ान के बाद उतरने वाला, दुनिया भर में एकल उड़ान भरने वाला पहला पायलट बन गया।
1934 बैंक लुटेरा जॉन डिलिंगर (चित्र), जिसके कारनामे पूरे अमेरिका में हुए, शिकागो में जीवनी थियेटर के बाहर पुलिस की गोली से मारे गए।
1944 पोलिश सरकार के निर्वासन के विरोध में, नेशनल लिबरेशन की पोलिश समिति ने अपने घोषणापत्र को प्रकाशित किया, जिसमें विदेशी सुधारों, नाजी जर्मनी के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने का सिलसिला, उद्योग का राष्ट्रीयकरण, और पश्चिम में एक सभ्य सीमा शामिल थी। ।
1964 अफ्रीकी एकता संगठन की दूसरी बैठक आयोजित की गयी।
1975 स्टेनली फॉर्मन ने फोटो फायर एस्केप कॉम्प्लेक्शन लिया, जो स्पॉट न्यूज़ फ़ोटोग्राफ़ी के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार और वर्ष का वर्ल्डवर्ल्ड प्रेस फोटो शीर्षक था।
1991 अमेरिकी सीरियल किलर जेफरी डेमर को विस्कॉन्सिन के विल्वायूकी में गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने उसके बक्से में मानव अवशेषों की खोज की।
1992 कोलम्बियाई ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार अपनी आलीशान जेल से भाग गया और अगले 17 महीने रन पर बिताए।
1993 1993 की महान बाढ़ के दौरान (बाढ़ का चित्रण), केस्कस्किया, इलिनोइस, अमेरिका के पास, टूट गया, पूरे शहर को सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स द्वारा संचालित बजारों को खाली करने के लिए मजबूर कर दिया।
1999 एमएसएन मैसेन्जर का पहला संस्करण माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी किया गया।
2000 एरिजोना विश्वविद्यालय के खलोलविदों ने बृहस्पति के 17वें प्राकृतिक उपग्रह की खोज की।
2002 इज़रायली रक्षा बलों ने हमास के सैन्य शाखा के नेता सलासाहेदे के घर पर एक बम गिराया, जिससे वह और उसके भाई मारे गए।
2005 लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने जीन चार्ल्स डी मेनेजेस को मार डाला, ब्राज़ीलियाई आप्रवासी, उसे गलत तरीके से शामिल करने के बाद शहर में दिन के असफल बमबारी प्रयासों में शामिल था।
2009 एक सूर्य ग्रहण, इतिहास में सबसे लंबा, 6 मिनट और 38.8 सेकंड तक चलता है, एशिया और प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों पर।

भारत की उभरती एकदलीय राजनीति में कांग्रेस के लिए खुला नया रास्ता

शेखर गुप्ता

महज दो सप्ताह पहले मैंने इसी स्तंभ में लिखा था कि कैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लोक सभा में बहुमत से दूर होने के बाद भी देश को एकदलीय व्यवस्था की ओर ले जा रही है। संसद के मॉनसून सत्र में इसका भी परीक्षण होगा। इस दौरान स्पष्ट हो सकता है कि भारत एकदलीय देश बनता जा रहा है। बेशक इसका दूसरा पहलू भी होगा। किसी दूसरी पार्टी के उभरने की संभावना भी होगी बशर्ते वह उन क्षेत्रीय पार्टियों के बचे-खुचे वोट बैंक को समेट ले, जिन्हें भाजपा या तो खत्म कर रही है या खुद में मिला रही है।

विडंबना है कि भाजपा की यह अविश्वसनीय जीत ही कांग्रेस को मौका देगी, जिससे वह देश भर में भगवा पार्टी को चुनौती देने वाली इकलौती पार्टी के रूप में अपनी ताकत फिर हासिल कर सकती है। मुझे पता है कि कांग्रेस के कट्टर विरोधी भी इस पर संशय करेंगे और बार-बार निराश हुए समर्थक भी। लेकिन मोदी, शाह और भाजपा इससे सहमत होंगे। उन्हें पता है कि उनके सामने चुनौती कांग्रेस से ही आती है। मोदी के हाल के वर्षों के चुनावी भाषण देखें। वह कांग्रेस और गांधी परिवार पर ही सबसे अधिक हमला करते हैं।

राज्यों के चुनावों में भी यही दिखता है। आंध्र प्रदेश में मोदी ने बार-बार कहा कि अपनी तुष्टीकरण की नीति के कारण कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया। झारखंड में कांग्रेसी मंत्री के सहयोगी के घरेलू सहायक के घर से नकदी बरामद होने का मामला उठाते हुए उन्होंने पूछा कि पार्टी ने अपने पैसे के गोदाम कहां-कहां बना रखे हैं। आंध्र प्रदेश में भी यही सवाल उठाया गया जहां कांग्रेस को 2024 के आम चुनाव में केवल 2.74 प्रतिशत वोट मिले। ओडिशा में जहां कांग्रेस का नामलेवा नहीं है, उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस का 'शहजादा' 2014 वाली स्क्रिप्ट ही पढ़ रहा है।'

बिहार में जहां कांग्रेस, यादव परिवार की सहयोगी है, उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए बार-बार उसे निशाना बनाया। जिस पश्चिम बंगाल में भाजपा की एकमात्र प्रतिद्वंद्वी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस थी, वहां उन्होंने कांग्रेस को उसके साथ जोड़ते हुए कहा कि दोनों ने मिलकर महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण रोकने की साजिश की।

चाहे ऐसा नगरपालिका चुनाव ही क्यों न हो, जहां कांग्रेस का वजूद ही नहीं, भाजपा वहां भी उसे ही निशाना बनाती है। यह प्रमाण है कि मोदी कांग्रेस को अपनी एकमात्र संभावित चुनौती मानते हैं। वे इतने चतुर हैं कि उसे नगण्य बताकर तिरस्कारपूर्वक खारिज नहीं करते।

मॉनसून सत्र में इस तर्क की परीक्षा इस बात से होगी कि भाजपा दलबदल, समावेशन या अनुपस्थिति के जरिये दो-तिहाई बहुमत जुटा पाती है या नहीं। और फिर संसद का आकार बढ़ाने, नया परिसीमन करने और उसके भीतर महिलाओं के आरक्षण विधेयक को पारित कराने के लिए आवश्यक संवैधानिक संशोधन कर पाती है या नहीं। अपनी केवल 240 सीटें होने के बाद भी 362 या उससे अधिक का दो-तिहाई बहुमत हासिल करना वाकई राजनीतिक चमत्कार होगा।

इसके बाद भाजपा की नजर अगले साल की शुरुआत में होने वाले उत्तर प्रदेश और



पंजाब तथा बाद में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनावों पर होगी। उसके अगले साल कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ होंगे। मैं लोकसभा में 10 से अधिक सदस्य देने वाले राज्य ही गिना रहा हूं। इनमें से अधिकांश में कांग्रेस ही भाजपा की मुख्य चुनौती होगी। इसलिए भाजपा का कांग्रेस-विरोधी सुर तीखा होता जाएगा।

लेकिन भाजपा की नजर 2029 और उससे आगे है। उसे प्रतिद्वंद्वी कौन लगता है? उसे 240 सीटों तक रोकने वाले क्षेत्रीय और जाति आधारित दलों में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के सिवा ज्यादातर खत्म हो चुके हैं। भाजपा ने उन्हें विभाजन, दलबदल या ऑपरेशन लोटस के जरिये खत्म कर दिया है। भाजपा से हारकर कोई क्षेत्रीय दल बच नहीं सका। द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) शायद अपनी विचारधारा के साथ जीवित रहे लेकिन तमिलनाडु में भाजपा का वजूद ही नहीं है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) ने भाजपा के साथ गठबंधन किया है। उनके प्रतिद्वंद्वी वाईएस जगन मोहन रेड्डी की युवजन श्रमिक रैयतु कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) भी भाजपा से नहीं लड़ेगी।

इंडिया ब्लॉक के कई सहयोगी दल या तो खत्म हो चुके हैं, टूट चुके हैं या छटपटा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास भविष्य के लिए चुनौती भी है और अवसर भी। क्या वह भाजपा को ललकारने वाली इकलौती पार्टी बनने का साहस कर सकती है? कांग्रेस के पास 21 प्रतिशत वोट का स्थायी बैंक है। भाजपा को 2024 में लगभग 37 प्रतिशत वोट मिले। कांग्रेस को 37 प्रतिशत तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। यदि वह केवल 5 प्रतिशत और जोड़ ले तो भाजपा का खेल बिगाड़ सकती है।

माना जा सकता है कि इनमे से ज्यादातर वोट भाजपा से ही आएंगे क्योंकि कांग्रेस के साथ मुकाबलों में भाजपा ही सबसे सफल रही है। भाजपा के वोट 30-32 प्रतिशत रह गए तो उसकी सीटें 200 तक सिमट जाएंगी। तब भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) बिल्कुल अलग होगा। हालांकि यह बात केवल कहने के लिए है मगर भाजपा इससे पूरी तरह वाकिफ है। यही कारण है कि प्रतिद्वंद्वी चाहे तृणमूल हो, बीजू जनता दल हो या वाईएसआरसीपी, उसकी दुश्मन कांग्रेस ही रहती है।

चूंकि हम सैद्धांतिक बात कर रहे हैं, इसलिए जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा जुलाई 2026 में प्रकाशित 'जर्नल ऑफ डेमोक्रेसी' में छपा राजनीति विज्ञानी एडगर सार और पेलिन आयन मुसिल का लेख पढ़ें। इसका शीर्षक भारत में बेहद अप्रत्याशित लगेगा जहां मजबूत सत्ताधारी पार्टी को हराने का इकलौता तरीका गठबंधन ही माना जाता है। कांग्रेस युग में भाजपा ने राजग बनाया और फिर कांग्रेस ने उसका जवाब संप्रग से दिया। लेकिन जॉन्स हॉपकिन्स का यह लेख हंगरी तथा तुर्किये के उदाहरण देकर तस्वीर उलट देता है।

लेखक कहते हैं, 'यह निबंध विद्वानों और रणनीतिकारों के बीच बनी उस सहमति को उलटता है कि प्रतिस्पर्धी अधिनायकवादी प्रणालियों में चुनाव पूर्व बने व्यापक गठबंधन ही प्रभुत्वशाली दलों को हटा सकते हैं।' उनके मुताबिक इसके सबूत दो चौंकाने वाले उलटफेरों में है। पहला हंगरी है, जहां 2026 में टिस्जा पार्टी ने अकेले ही ऑर्बान की फिदेज को पराजित किया और दूसरा तुर्किये है, जहां 2024 में रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी ने अकेले लड़कर ऐतिहासिक स्थानीय चुनाव जीते।

हंगरी में फिदेज के असंतुष्ट पीटर माग्यार ने नई पार्टी बनाई और ऑर्बान को केवल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। विचारधारा में वह भी ऑर्बान जितने ही दक्षिणपंथी हैं। तुर्किये में रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी ने खुद को नया रूप दिया और 'विस्तृत विपक्षी मतदाता वर्ग' को अपने भीतर समेट लिया। यह मतदाता वर्ग अहम है। यह भारत सहित हर लोकतंत्र में होता है। इस वोट को एकजुट करने के लिए विपक्ष ने अभी तक बहुदलीय गठबंधन बनाने की कोशिश की है। क्या कांग्रेस अब अकेले हिम्मत कर सकती है?

हमने श्रीलंका और नेपाल में देखा कि ताकतवर सत्ताधारियों को हराया जा सकता है। मैं बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा क्योंकि वहां चुनाव सत्ताधारी दल पर प्रतिबंध लगाने के बाद हुए। श्रीलंका और नेपाल में नए नेता नई सोच तथा एकदलीय चुनौती के साथ आए।

क्या कांग्रेस खुद को नए सिरे से गढ़ सकती है? वाम-दक्षिण का द्वंद्व काम नहीं करेगा क्योंकि कल्याणकारी योजनाओं, वितरणवादी अर्थशास्त्र, सार्वजनिक क्षेत्र और सब्सिडी के मामले में मोदी कांग्रेस से भी अधिक वामपंथी हैं। मोदी की नीतियों, विदेशी सम्मान पाने की प्रवृत्ति, भाषा, शैली का मजाक उड़ाने से सोशल मीडिया पर रीट्वीट तो मिल सकते हैं मगर मोदी के कारण भाजपा को मिलने वाले 15 प्रतिशत वोट अधिक वोटों पर फर्क नहीं पड़ेगा।

कांग्रेस को नई सोच और एजेंडा चाहिए। वह कहती है कि भाजपा चीन और डॉनल्ड ट्रंप के सामने झुक रही है, पाकिस्तान से नहीं लड़ सकती, इजरायल से बहुत मित्रवत है लेकिन कांग्रेस खुद इन सबका सामना कैसे करेगी? बदली हुई दुनिया में कांग्रेस की विदेश नीति, सामरिक नीति और आर्थिक नीति क्या होगी? वह कहती है कि मोदी के वृद्धि के आंकड़े झूठे हैं। तो वह भारत को 8 प्रतिशत वृद्धि दर तक कैसे ले जाएगी?

सबसे बड़ी विडंबनाएं अक्सर सबसे कठोर हकीकतों में छिपी होती हैं जैसे सबसे बड़े संकट में अवसर छिपे होते हैं। क्षेत्रीय दलों के जाने के बाद नया एकदलीय तंत्र अब दो दलीय मुकाबले का रास्ता खोल सकता है। बस, चुनौती देने वाली पार्टी में सत्ताधारी को अकेले चुनौती देने के लिए साहस, महत्त्वाकांक्षा और नई सोच होना जरूरी है।

लोकतंत्र की तस्वीर के दो समानांतर दृश्य चिंताजनक

ज्योति भास्कर

संसद भवन के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव, जबकि भीतर मानसून सत्र का पहला दिन हंगामे और स्थगनों की भेंट चढ़ना- सोमवार को राजधानी में लोकतंत्र की तस्वीर के ये दो समानांतर दृश्य चिंताजनक तो हैं ही, ये उस लोकतांत्रिक चुनौती के भी संकेत हैं, जिसमें संवाद का स्थान धीरे-धीरे टकराव लेता जा रहा है। यह निर्विवाद है कि संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने और सरकार की नीतियों का विरोध करने का अधिकार देता है। अगर हजारों छात्र, अभिभावक, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक दल अपनी चिंताएं व्यक्त करने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, तो उनकी बात सुनी ही जानी चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती भी इसी में है कि असहमति को स्थान मिले और सरकारें जनभावनाओं के प्रति संवेदनशील हों। लेकिन, यह भी उतना ही आवश्यक है कि प्रदर्शन संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर हो। यदि भीड़ संसद जैसे अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र तक पहुंचने का प्रयास करती है, तो सुरक्षा एजेंसियों का सतर्क होना स्वाभाविक है। साथ ही, यह आशंका भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती कि प्रदर्शनकारियों की आड़ में असामाजिक तत्व घुसपैठ कर अराजकता फैलाने का प्रयास कर सकते हैं। संसद के भीतर की स्थिति भी कम निराशाजनक नहीं रही। मानसून सत्र का पहला ही दिन कई बार हंगामे और स्थगन की भेंट चढ़ना इस बात का संकेत है कि राजनीतिक दलों के बीच संवाद का संकट गहराता जा रहा है। जब सदन में



सार्थक बहसों का स्थान नारेबाजी और व्यवधान लेने लगते हैं, तो लोकतांत्रिक जवाबदेही का सबसे अहम मंच कमजोर पड़ने लगता है। सदन के सफल संचालन की जिम्मेदारी जितनी सरकार की है, उतनी ही विपक्षी दलों की भी। सरकार का दायित्व है कि वह विपक्ष को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर दे, तो विपक्ष की भूमिका केवल विरोध करने तक सीमित न रहकर, सरकारी नीतियों की तथ्यपरक और रचनात्मक समीक्षा करना भी है। संसद लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है, तो सड़क, लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का सबसे स्वाभाविक मंच। यह भी ध्यान रखना होगा कि संसद और सड़क एक-दूसरे के विकल्प नहीं, बल्कि पूरक हैं। सड़क पर उठने वाली आवाजें संसद तक पहुंचनी चाहिए और संसद में होने वाली बहसों का समाधान जनता के बीच दिखाई देना चाहिए। लेकिन अगर हर समस्या का समाधान केवल सड़क पर शक्ति प्रदर्शन या संसद में गतिरोध के रूप में खोजा जाएगा, तो लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का भरोसा ही प्रभावित होगा। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में विचारों का टकराव स्वाभाविक है, पर लोकतंत्र की शक्ति किसी एक पक्ष की जीत में नहीं, बल्कि इस क्षमता में निहित है कि मतभेदों के बावजूद संवाद जारी रहे।

पवार को अपनी पार्टी में आंतरिक संघर्षों का सामना

कल्याणी शंकर

संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही एन.सी.पी. (राकांपा) के नेता शरद पवार अपनी पार्टी के भीतर आंतरिक संघर्षों का सामना कर रहे हैं। पहले महाराष्ट्र में राजनीतिक बदलाव हो सकते हैं और फिर विलय के बाद राकांपा भाजपा के साथ गठबंधन कर सकती है। पवार को एक राजनीतिक 'सर्वाइवर' के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने अक्सर अपनी पार्टी को खत्म होने से बचाया है। वह अप्रत्याशित गठबंधन बनाने में कुशल हैं, जैसे कि 2019 का महा विकास अघाड़ी गठबंधन, जिसमें शिवसेना और कांग्रेस शामिल थीं। महाराष्ट्र में उनका जमीनी स्तर पर मजबूत नैटवर्क भी है। अपने भतीजे अजीत पवार को एक विमान दुर्घटना में खोने की दुखद घटना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अपने गुट के भीतर चल रहे सत्ता संघर्ष के बावजूद, उनका राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों की राजनीति में महत्वपूर्ण प्रभाव बना हुआ है।

जुलाई, 2023 में महाराष्ट्र में राजनीतिक माहौल तब और खराब हो गया, जब अजीत पवार ने भाजपा-शिवसेना सरकार में शामिल होने के लिए राकांपा छोड़ दी। जल्द ही, चुनाव आयोग ने अजीत पवार के समूह को आधिकारिक राकांपा के रूप में मान्यता दे दी। जवाब में शरद पवार ने 'राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) नाम से एक नई पार्टी शुरू की। अब, महाराष्ट्र में 2 प्रतिद्वंद्वी पार्टियां हैं, जो दोनों एक ही राजनीतिक विरासत पर दावा कर रही हैं। यह सत्र एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आया है, जहां संसदीय प्रतिनिधित्व पर आने वाला कानून शासन को नया रूप दे सकता है और विवाद के बावजूद बदलाव की उम्मीद जगा सकता है।

विधायी प्रक्रिया में पवार की भागीदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में संसदीय प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने वाला आगामी विधेयक महाराष्ट्र के प्रभाव को काफी बदल सकता है। यह विधेयक लोकसभा सीटों को 550 से बढ़ाकर 850 करने और



जनगणना-आधारित परिसीमन शक्तियों को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखता है। यह विधेयक संसद में लोगों का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाए, इस पर चल रही बातचीत में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह महाराष्ट्र और दक्षिणी राज्यों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां लोग निष्पक्ष प्रतिनिधित्व पाने और संसाधनों को सांझा करने को लेकर चिंतित हैं। विधेयक में संसदीय सीटों की संख्या 543 से बढ़ा कर 850 करने और जनगणना डाटा की रिपोर्टिंग के लिए नए नियम पेश करने का प्रस्ताव है। इन बदलावों का इन क्षेत्रों के राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा असर पड़ सकता है।

शरद पवार के पास गठबंधन बनाने और हितधारकों की ड्क्षचताओं का समाधान करने का अवसर है, जो संसद के समर्थन को प्रभावित करने की उनकी क्षमता में विश्वास और आशावाद को बढ़ावा दे सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक धुरी के रूप में, पवार ने अपनी राकांपा के भीतर आंतरिक विभाजनों के बीच लचीलापन दिखाया है। जनवरी, 2026 में एक विमान दुर्घटना में अपने भतीजे अजीत पवार के दुखद निधन के बाद, पार्टी के पास उत्तराधिकार की चुनौतियों का समाधान करने का मौका है, जिसमें अजीत की पत्नी सुनेत्रा पवार, उपमुख्यमंत्री और राज्य पार्टी प्रमुख की भूमिकाओं में आ रही हैं। इन चुनौतियों और चल रहे गुटीय मुद्दों का सामना करने के बावजूद, शरद पवार का राकांपा पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। यह स्थिति पार्टी के लिए भविष्य के विधानसभा चुनावों में सफल होने के लिए फिर से संगठित होने और नवीन रणनीतियां विकसित करने का एक महत्वपूर्ण समय है।

पवार पर एन.डी.ए.-गठबंधन वाले एन.सी. गुट के साथ विलय करने का दबाव है। हालांकि समाधान की उनकी खोज स्थिरता की उम्मीद जगाती है, साथ ही चल रहे गुटीय संघर्षों पर चिंता भी पैदा करती है। यह स्थिति दर्शाती है कि पवार विपक्ष के भीतर एकता बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और उन्होंने जानबूझकर किसी भी विलय की योजना को त्याग दिया है। उनके कार्य न केवल उनके नेतृत्व को मजबूत करते हैं, बल्कि महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिरता के लिए उनके समर्थन को भी प्रदर्शित करते हैं, जिससे उनके संकल्प में विश्वास बढ़ता है। शरद पवार गुट के पास लोकसभा में 8 सांसद हैं और एन.डी.ए. द्वारा अपना बहुमत मजबूत करने के प्रयास में वे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह समूह महत्वपूर्ण कानूनों को पारित करने के लिए अहम हो सकता है, जैसे कि महिला आरक्षण विधेयक, जो संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव करता है। यदि पवार का गुट इन सुधारों का समर्थन करता है, तो यह उनके कार्यान्वयन को काफी प्रभावित कर सकता है और अब और भविष्य में विधायी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। शरद पवार अपनी व्यापक राजनीतिक यात्रा पर विचार करते हैं। वह राजनीति में क्षणिक पलों के महत्व को नोट करते हैं, जिन्होंने 'कई सूर्योदय और सूर्यास्त देखे हैं' और महाराष्ट्र के बदलते परिदृश्य के बीच अपने भविष्य के गठबंधनों को लेकर सतर्क रहते हैं। पर्यवेक्षक और राजनीतिक विश्लेषक बारीकी से देख रहे हैं कि क्या पवार का गुट एन.डी.ए. के साथ गठबंधन करेगा या एक जटिल, विकसित हो रहे राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढना जारी रखेगा, जो महाराष्ट्र और उससे आगे के शासन को नया रूप दे सकता है। वर्तमान में, विलय या गैर-प्रकटीकरण समझौते (एन.डी.ए.) की स्थापना के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। हालांकि, घटनाओं की शृंखला-जैसे चल रही विलय चर्चाओं की खबरें, विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं के बीच बैठकें और मंगलवार रात फडनवीस के साथ एक अलग चर्चा-संकेत देती है कि पर्दे के पीछे बातचीत अभी भी चल रही है।

क्या 15 साल की सत्ता भी जवाबदेही तय नहीं कर सकी?

सत्येंद्र प्रताप सिंह

21 जुलाई पश्चिम बंगाल की राजनीति में केवल एक तारीख नहीं है। यह एक ऐसी घटना का प्रतीक है जिसने राज्य की राजनीति की दिशा बदल दी। 21 जुलाई 1993 को कोलकाता में युवा कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में 13 लोगों की मौत हुई थी। उस समय ममता बनर्जी कांग्रेस की सबसे आक्रामक युवा नेता थीं। उन्होंने इस घटना को लोकतंत्र पर हमला बताया और हर वर्ष 21 जुलाई को %शहीद दिवस% के रूप में मनाना शुरू किया। यही आंदोलन आगे चलकर तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक पहचान का सबसे मजबूत आधार बना।

विपक्ष में रहते हुए ममता बनर्जी का सबसे बड़ा आरोप था कि तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार ने निर्दोष प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवाईं और दोषियों को बचाया। उन्होंने बार-बार न्यायिक जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसलिए जब 2011 में 34 वर्षों के वाम शासन का अंत हुआ और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनीं, तो स्वाभाविक रूप से यह उम्मीद जगी कि 1993 की घटना का सच सामने आएगा और दोषियों की जवाबदेही तय होगी।

इसी उद्देश्य से मई 2011 में राज्य सरकार ने ओडिशा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुशांत चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया। उस समय इसे केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि राजनीतिक और नैतिक प्रतिबद्धता के रूप में देखा गया।

आयोग को यह जांच करनी थी कि 21 जुलाई 1993 को वास्तव में क्या हुआ था। क्या पुलिस के पास गोली चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था? किस स्तर पर फायरिंग का निर्णय लिया गया? क्या पुलिस ने कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की या आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया गया? क्या प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर कोई ऐसी चूक हुई जिसकी वजह से 13 लोगों की जान गई? इन सवालों के जवाब केवल इतिहास के लिए नहीं,



बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य की जवाबदेही तय करने के लिए भी महत्वपूर्ण थे।

आयोग की कार्यवाही कई वर्षों तक चली। लगभग 350 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इनमें पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक नेता, प्रत्यक्षदर्शी, पत्रकार और मृतकों के परिजन शामिल थे। उस समय के अनेक प्रभावशाली राजनीतिक और प्रशासनिक चेहरों को आयोग के सामने उपस्थित होना पड़ा। माकपा के तत्कालीन राज्य सचिव बिमान बोस, ज्योति बसु सरकार में मंत्री रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य तथा तत्कालीन गृह सचिव मनीष गुप्ता जैसे प्रमुख व्यक्तियों ने अपने बयान दर्ज कराए।

26 फरवरी 2014 को आयोग के सामने पेश हुए बुद्धदेव भट्टाचार्य ने लगभग 50 मिनट तक अपना पक्ष रखा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उस समय उन्हें पुलिस कार्रवाई गलत नहीं लगी थी और आज भी उनका मत नहीं बदला है। दूसरी ओर तत्कालीन गृह सचिव मनीष गुप्ता ने कहा कि वे पुलिस फायरिंग के पक्ष में नहीं थे। इन बयानों ने उस समय की निर्णय प्रक्रिया को लेकर कई नए प्रश्न खड़े किए। आयोग ने तत्कालीन पुलिस आयुक्त तुषार तालुकदार, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डीसी वाजपेयी, संयुक्त पुलिस आयुक्त आरके जोहरी, दक्षिण डिवीजन के तत्कालीन उपायुक्त एनके सिंह तथा राइटर्स बिल्डिंग की सुरक्षा के प्रभारी संयुक्त पुलिस आयुक्त कंवलजीत सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया।

लेकिन जांच आसान नहीं रही। तीन सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारियों ने आयोग के समन को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी। अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए आयोग की कार्यवाही के एक हिस्से पर रोक लगा दी। इससे जांच की प्रक्रिया लंबी और जटिल होती चली गई।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुशांत चट्टोपाध्याय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर टिप्पणी की कि पुलिस कार्रवाई बिना उकसावे की गई और असंवैधानिक प्रतीत होती है। उन्होंने यहां तक कहा कि यह मामला जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक गंभीर दिखाई देता है। यह टिप्पणी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी। हालांकि किसी भी न्यायिक आयोग की अंतरिम टिप्पणियां अंतिम निर्णय नहीं मानी जातीं। अंतिम निष्कर्ष उसकी पूरी रिपोर्ट में दर्ज होते हैं।

लंबी सुनवाई के बाद आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी। इसके बाद उम्मीद थी कि सरकार रिपोर्ट सार्वजनिक करेगी, उसकी सिफारिशों पर चर्चा होगी और यदि किसी अधिकारी या राजनीतिक व्यक्ति की जिम्मेदारी तय हुई है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। सरकार ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि आयोग ने क्या निष्कर्ष निकाले और किन सिफारिशों की अनुशंसा की। न तो विधानसभा में इस पर कोई विस्तृत चर्चा हुई और न ही कोई श्वेतपत्र जारी किया गया। परिणामस्वरूप आयोग की वर्षों की मेहनत जनता की पहुंच से बाहर रह गई।

यहीं से सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक प्रश्न शुरू होता है। यदि ममता बनर्जी विपक्ष में रहते हुए इस घटना को न्याय का सबसे बड़ा मुद्दा बनाती थीं, यदि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने स्वयं जांच आयोग गठित किया, यदि आयोग ने वर्षों तक सुनवाई कर रिपोर्ट सौंप दी, तो फिर दोषियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या आयोग ने किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी तय नहीं की थी? यदि की थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यदि नहीं की थी तो सरकार ने यह बात सार्वजनिक क्यों नहीं की? यदि कानूनी अड़चनें थीं तो जनता को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई?

भारतीय रेलवे में नई हाइड्रोजन क्रांति

मृत्युंजय दीक्षित

जुलाई 17, 2026 का दिन भारतीय रेलवे के लिए एक स्मरणीय दिन बन गया है क्योंकि इस दिन रेल यातायात में विकसित भारत के नये युग का सूत्रपात हुआऔर भा रत को हाइड्रोजन ट्रेन का उपहार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन किया। अब भारत उन चुनिन्दा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनों का संचालन हो रहा है। अभी तक जर्मनी, फ्रांस और चीन जैसे देश ही इस प्रकार की ट्रेनों का संचालन कर रहे थे । जींद-सोनीपत मार्ग पर चलने वाली यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली 10 कोच और 3,200 हार्स पावर क्षमता वाली दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों मे शामिल है। यह ट्रेन पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से तैयार की गई है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलने वाली इस ट्रेन में हाइड्रोजन से बिजली बनाई जाती है जिससे ट्रेन संचालित होती है। इस प्रक्रिया में केवल जलवाष्प निकलती है इसलिए इससे शून्य कार्बन उत्सर्जन होता है। यह ट्रेन डीजल ट्रेनों की तुलना में प्रदूषण नहीं फैलाती, आवाज भी कम करती है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करती है। इसके लिए पारंपरिक इलेक्ट्रिक ट्रेनों की तरह मार्ग पर ओवरहेड बिजली लाईन की जरूरत भी नहीं होती क्योकि बिजली ट्रेन के भीतर ही तैयार होती है। ऐसी ट्रेनों के संचालन से कोयला आधारित बिजली उत्पादन पर निर्भरता कम होगी। यह 10 कोच वाली दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेनों में शामिल है। यह अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ट्रेन है जो बाहर से देखने में तो साधारण ट्रेनों की तरह ही लगती है किन्तु जब यात्री ट्रेन के कोच में बैठकर यात्रा करते हैं तो उन्हें एक अलग प्रकार की सुखद अनुभूति होती है। ट्रेन में आधुनिक सुरक्षा प्रणाली, हाइड्रोजन लीक डिटेक्शन सिस्टम और विशेष फ्यूल सेल तकनीक का उपयोग किया गया है। इस ट्रेन में यात्रियों के लिए टिकट का मूल्य 5 से 25 रुपए तक रखा गया है ताकि आम से खास तक सभी वर्ग के लोग इस पूर्ण रूप से स्वदेशी तथा प्रदूषण रहित ट्रेन की आरामदायक यात्रा का लाभ उठा सकें। भारतीय रेलवे की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में जींद से सोनीपत के बीच 89 किमी प्रतिदिन दो राउंड ट्रिप यानी कुल 356 किमी का सफर तय करेगी। यह हाइड्रोजन ट्रेन जींद सिटी, गोहाना, पांडु पिंडारा, ललित खेड़ा, भंभेवा, इसापुर खेड़ी, बुटाना, खंडराई, राबरा, लाथ, मोहाना और सोनीपत स्टेशन पर रुकेगी। भारत की स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन अन्य देशों की तुलना में सबसे कम लागत मात्र 136 करोड़ रुपए में बनी है। ट्रेन की सामान्य ऑपरेशनल स्पीड 75 किमी प्रति घंटा होगी। ट्रायल रन के दौरान इसने 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार प्राप्त की थी। यह ट्रेन एक घंटे में 90 किमी का सफर तय कर सकती है। जबकि कई पुराने डीजल इंजन वाली ट्रेनों को इतनी दूरी तय करने में लगभग दो घंटे लग जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे में व्यापक बदलाव लाने का संकल्प लिया था जो अब धरातल पर उतरता दिख रहा है। भारतीय रेलवे आगामी वर्षों में और भी आधुनिक बनने की तैयारी कर रहा है। सरकार का लक्ष्य व संकल्प भारतीय रेलवे को अधिक सुरक्षित, तेज और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है यह हाइड्रोजन ट्रेन उसी लक्ष्य की दिशा में ले जाने वाली पहल है। **संक्षिप्त इतिहास** - भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे के बीच चलाई गई थी। यह ट्रेन 34 किमी की दूरी तय करती थी इसमें 14 डिब्बे थे1 960 में भारतीय रेलवे ने डीजल इंजनों को अपनाना शुरू किया। इन इंजनों की मदद से लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ। मालगाड़ियों की क्षमता बढ़ी और रेलवे का विस्तार पहले की तुलना में तीव्रगति से हुआ।

क्यों होते है माला में 108 दाने, रुद्राक्ष से बनी माला मंत्र जप के लिए सर्वश्रेष्ठ क्यों

हिन्दू पौराणिक शास्त्रों के अनुसार हम मंत्र जप के लिए जिस माला का उपयोग करते है, उसमें दानों की संख्या 108 होती है। शास्त्रों में 108 संख्या का अत्यधिक महत्व है। इसके पीछे कई धार्मिक, ज्योतषिक और वैज्ञानिक मान्यताएं हैं, कि माला में 108 ही दाने क्यों होते हैं। आइए हम यहां जानते है ऐसी ही कुछ मान्यताओ के बारे में और जानेंगे आखिर माला का प्रयोग क्यों करना चाहिए मन्त्र जाप के लिए।



हिन्दू ग्रंथों के अनुसार रुद्राक्ष से बनी माला मंत्र जप के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। रुद्राक्ष को महादेव का प्रतीक माना गया है। रुद्राक्ष में सूक्ष्म कीटाणुओं का नाश करने की शक्ति भी होती है और रुद्राक्ष वातावरण में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करके साधक के शरीर में पहुंचा देता है। रुद्राक्ष से अलग यह माला तुलसी, स्फटिक, मोती या नगों से भी बनी होती है। प्राचीन काल से ही बडे-बडे तपस्वी, साधु-संत इस उपाय को अपनाते रहे हैं।

भगवान की पूजा के लिए कुश का आसन बहुत जरूरी है, इसके बाद दान-पुण्य जरूरी है। जब भी मंत्र जप करें, माला का उपयोग अवश्य करना चाहिए। माला के बिना संख्याहीन किए गए मंत्र जप का भी पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। जो भी व्यक्ति माला की मदद से मंत्र जप करता है, उसकी मनोकामनएं बहुत जल्द पूर्ण होती हैं। मंत्र जप निर्धारित संख्या 108 के अनुसार किए जाए तो सर्व श्रेष्ठ रहता है। शास्त्रों के अनुसार एक पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति दिनभर में जितनी बार सांस लेता है, व्यक्ति के सांस से ही माला के दानों की संख्या 108 का संबंध है। सामान्यत: 24 घंटे में एक व्यक्ति करीब 21600 बार सांस लेता है। दिन के 24 घंटों में से 12 घंटे दैनिक कार्यों में व्यतीत हो जाते हैं और शेष 12 घंटों में व्यक्ति सांस लेता है 10800 बार। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को हर सांस पर यानी पूजन के लिए निर्धारित समय 12 घंटे में 10800 बार ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, लेकिन यह संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए 10800 बार सांस लेने की संख्या से अंतिम दो शून्य हटाकर जप के लिए 108 संख्या निर्धारित की गई है। इसी संख्या के आधार पर जप की माला में 108 दाने होते हैं।

वैज्ञानिक महत्त्व:

वैज्ञानिकों के अनुसार माला के 108 दाने और सूर्य की कलाओं का गहरा संबंध है। एक वर्ष में सूर्य 216000 कलाएं बदलता है और वर्ष में दो बार अपनी स्थिति भी बदलता है। छह माह उत्तरायण रहता है और छह माह दक्षिणायन। अत: सूर्य छह माह की एक स्थिति में 108000 बार कलाएं बदलता है। इसी संख्या 108000 से अंतिम तीन शून्य हटाकर माला के 108 मोती निर्धारित किए गए हैं। माला का एक-एक दाना सूर्य की एक-एक कला का प्रतीक है। सूर्य ही व्यक्ति को तेजस्वी बनाता है, सूर्य ही एकमात्र साक्षात दिखने वाले देवता हैं, इसी वजह से सूर्य की कलाओं के आधार पर दानों की संख्या 108 निर्धारित की गई है।

माला के दानों की संख्या 108 संपूर्ण ब्रहमांड का प्रतिनिधित्व करती है। ज्योतिष के अनुसार सम्पूर्ण ब्रहमांड को 12 भागों (राशियों) में विभाजित किया गया है। इन 12 भागों (राशियों) के नाम मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर,कुंभ और मीन हैं। इन 12 राशियों में नौ ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु विचरण करते हैं। अत: विचरण ग्रहों की संख्या 9 का गुणा 12 राशियों की संख्या में किया जाए तो संख्या 108 प्राप्त हो जाती है। ज्योतिष के अनुसार इसी संख्या के आधार पर जप की माला में 108 दाने होते हैं।

षियों के अनुसार

एक अन्य मान्यता के अनुसार ऋषियों ने में माला में 108 दाने रखने के पीछे ज्योतिषी कारण बताया है। शास्त्रों के अनुसार कुल 27 नक्षत्र बताए गए हैं। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और 27 नक्षत्रों के कुल चरण 108 ही होते हैं। माला का एक-एक दाना नक्षत्र के एक-एक चरण का प्रतिनिधित्व करता है। मंत्र जप की माला में सबसे ऊपर एक बडा दाना होता है जो कि सुमेरू कहलाता है। सुमेरू से ही जप की संख्या प्रारंभ होती है और यहीं पर खत्म भी। जप का एक चक्र पूर्ण होकर सुमेरू दाने तक पहुंच जाता है तब माला को पलटा लिया जाता है। सुमेरू को कभी भी लांघना नहीं चाहिए। जब भी मंत्र जप पूर्ण करें तो सुमेरू को माथे पर लगाकर नमन करना चाहिए। इससे जप का पूर्ण फल प्राप्त होता है।

इस तरह के उपाय से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है

शैनागम एवं अन्य दर्शन साहित्य में भी इन्हीं पंच तत्वों की प्रमुखता है। चीनी फेंगशुई में केवल दो तत्वों की प्रधानता है- वायु एवं जल की। वस्तुत: ये पंचतत्व सनातन हैं। ये मनुष्य ही नहीं बल्कि संपूर्ण चराचर जगत पर प्रभाव डालते हैं।



अथर्ववेद में कहा गया है-
पन्चवाहि वहत्यग्रमेशां प्रष्टयो युक्ता अनु सवहन्त।
अयातमस्य दस्ये नयातं पर नेदियोवर दवीय ॥ 10 /8 ॥

लक्ष्मी आगमन के विशेष वास्तु उपचार । वास्तु शास्त्र का आधार प्रकृति है। आकाश, अग्नि, जल, वायु एवं पृथ्वी इन पांच तत्वों को वास्तु-शास्त्र में पंचमहाभूत कहा गया है। शैनागम एवं अन्य दर्शन साहित्य में भी इन्हीं पंच तत्वों की प्रमुखता है। चीनी फेंगशुई में केवल दो तत्वों की प्रधानता है- वायु एवं जल की। वस्तुत: ये पंचतत्व सनातन हैं। ये मनुष्य ही नहीं बल्कि संपूर्ण चराचर जगत पर प्रभाव डालते हैं। वास्तु शास्त्र पकृति के साथ सामंजस्य एवं समरसता रखकर भवन निर्माण के सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। ये सिद्धांत मनुष्य जीवन से गहरे जुडे हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर पृथ्वी, जल, तेज (अग्नि), प्रकाश, वायु व आकाश को रचकर, उन्हें संतुलित रखकर संसार को नियमपूर्वक चलाते हैं। मननशील विद्वान लोग उन्हें अपने भीतर जानकर संतुलित हो प्रबल प्रशस्त रहते हैं। इन्हीं पांच संतुलित तत्वों से निवास गृह व कार्य गृह आदि का वातावरण तथा वास्तु शुद्ध व संतुलित होता है, तब प्राणी की प्रगति होती है।

गृह निर्माण इस प्रकार का हो कि सूर्य का प्रकाश सब दिशाओं से आए तथा सब प्रकार से ऋतु अनुकूल हो, ताकि परिवार स्वस्थ रहे। राह चलता राहगीर भी अंदर न झांक पाए, न ही गृह में वास करने वाले बाहर वालों को देख पाएं। ऐसे उत्तम गृह में गृहिणी की निज संतान उत्तम ही उत्तम होती है। वास्तु शास्त्र तथा वास्तु कला का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार वेद और उपवेद हैं।

गृह के मुख्य द्वार को गृहमुख माना जाता है। इसका वास्तु शास्त्र में विशेष महत्व है। यह परिवार व गृहस्वामी की शालीनता, समृद्धि व विद्वत्ता दर्शाता है। इसलिए मुख्य द्वार को हमेशा बाकी द्वारों की अपेक्षा बडा व सुसज्जित रखने की प्रथा रही है। पौराणिक भारतीय संस्कृति के अनुसार इसे कलश, नारियल व पुष्प, केले के पत्र या स्वास्तिक आदि से अथवा उनके चित्रों से सुसज्जित करना चाहिए।

मुख्य द्वार चार भुजाओं की चौखट वाला हो। इसे दहलीज भी कहते हैं। इससे निवास में गंदगी भी कम आती है तथा नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं कर पातीं। प्रात: घर का जो भी व्यक्ति मुख्य द्वार खोले, उसे सर्वप्रथम दहलीज पर जल छिडकना चाहिए , ताकि रात में वहां एकत्रित दूषित ऊर्जाएं घुलकर बह जाएं और गृह में प्रवेश न कर पाएं।

गृहिणी को चाहिए कि वह प्रात:

सर्वप्रथम घर की साफ-सफाई करे या कराए। तत्पश्चात स्वयं नहा-धोकर मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर एकदम सामने स्थल पर सामर्थ्य के अनुसार रंगोली बनाए। यह भी नकारात्मक ऊर्जाओं को रोकती है। मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर केसरिया रंग से 9ग9 परिमाण का स्वास्तिक बनाकर लगाएं। मुख्य प्रवेश द्वार को हरे व पीले रंग से रंगना वास्तुसम्मत होता है। खाना बनाना शुरू करने से पहले पाकशाला का साफहोना अति आवश्यक है। रोसोईये को चाहिए कि मंत्र पाठ से ईश्वर को याद करे और कहे कि मेरे हाथ से बना खाना स्वादिष्ट तथा सभी के लिए स्वास्थ्यवर्द्धक हो। पहली चपाती गाय के, दूसरी पक्षियों के तथा तीसरी कुत्ते के निमित्त बनाए। तदुपरांत परविार का भोजन आदि बनाए।

निवास गृह या कार्यालय में शुद्ध ऊर्जा के संचार हेतुप्रात:

व सायं शंख-ध्वनि करें। गुग्गुल युक्त धूप व अगरवत्ती प्रज्वलित करें तथा क्क का उच्चारण करते हुए समस्त गृह में धूम्र को घुमाएं। प्रात: काल सूर्य को अर्य देकर सूर्य नमस्कार अवश्य करें। यदि परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अनकूल रहेगा, तो गृह का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। ध्यान रखें, आईने व झरोखों के शीशों पर धूल नहीं रहे। उन्हें प्रतिदिन साफरखें। गृह की उत्तर दिशा में विभूषक फव्वारा या मछली कुंड रखें। इससे परिवार में समृद्धि की वृद्धि होती है।

मोहिनी के पुत्र हैं भगवान अय्यप्पा



श्रीहरि ने मोहिनी अवतार लिया था। उन्होंने यह अवतार तब लिया, जब समुद्र मंथन से अमृत निकला था। और देवताओं और दानवों में यह वितरित करना था। हालांकि मोहिनी अवतार में श्रीहरि ने छल से देवताओं को अमृत और दानवों को अन्य द्रव्य पिलाया था। पौराणिक मतानुसार दरअसल विष्णु जी के मोहनी रूप को ही अय्यप्पा की मां माना जाता है।

श्रीहरि का मोहिनी रूप काफी आकर्षक था। उन्होंने यह रूप लोककल्याण के लिए लिया था। इस रूप में श्रीहरि एक बहुत सुंदर युवा स्त्री के रूप में प्रकट हुए थे। अग्नि पुराण 3.12 में वर्णित है कि अमृत वितरण के लिए श्रीहरि यानी विष्णु जी द्वारा मोहिनी रूप धारण किया गया। और इसी समय भगवान शिव मोहिनी रूप पर आसक्त होकर स्लखित हो गए थे। किंवदंती है कि जहां शिव स्खलित हुए वह स्थान गंगोत्री था। दरअसल यह तत्व ही अमुल्य पारद तत्व है। गंगाजल के कण-कण में पारद है। हिंदू शास्त्रानुसार यह पारद ही है जो संपूर्ण जगत के सृर्जन का मूलाधार है क्योंकि यह संसार आदि शक्ति के रज अर्थात गंधक और शिव की वीर्य अर्थात पारद से बना है।

वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार यह तिथि सब पापों को हरने वाली और उत्तम है । इस दिन जो व्रत रहता है उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पापों से छुटकारा पा जाते हैं।

इसकी विधि -

जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत करे, उसे एकदिन पूर्व अर्थात दशमी तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत के दिन एकादशी तिथि में व्रती को सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और नित्य कर्म कर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। स्नान के लिये किसी पवित्र नदी या सरोवर का जल मिलना श्रेष्ठ होता है। अगर यह संभव न हों तो घर में ही जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के लिये कुश और तिल के लेप का प्रयोग करना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन भगवान श्रीविष्णु के साथ-साथ भगवान श्रीराम की पूजा भी की जाती है। व्रत का संकल्प लेने के बाद ही इस व्रत को शुरु किया जाता है। संकल्प लेने के लिये इन दोनों देवों के समक्ष संकल्प लिया जाता है। देवों का पूजन करने के लिये कलश स्थापना कर, उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बांध कर पहले कलश का पूजन किया जाता है।

इसके बाद इसके ऊपर भगवान कि तस्वीर या प्रतिमा रखें तत्पश्चात भगवान की प्रतिमा को स्नानादि से शुद्ध कर उत्तम वस्त्र पहनाना चाहिए। फिर धूप, दीप से आरती उतारनी चाहिए और मीठे फलों का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद प्रसाद वितरीत कर ब्राहमणों को भोजन तथा दान दक्षिणा देनी चाहिए। रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए मूर्ति के समीप ही शयन करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत रखने वाले को अपना मन साफरखना चाहिए। प्रात: काल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की मूर्ति अथवा तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं और तुलसी, फल, तिल सहित भगवान की पूजा करें। व्रत रखने वाले को स्वयं तुलसी पत्ता नहीं तोडना चाहिए। किसी के प्रति मन में द्वेष की भावना न लाएं और न ही किसी की निंदा करें। व्रत रखने वाले को पूरे दिन निराहार रहना चाहिए। शाम में पूजा के बाद चाहें तो फलाहार कर सकते हैं। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का बडा महत्व है। संभव हो तो रात में जागकर भगवान का भजन कीर्तन करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राहमण को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करें।

इस व्रत के पुण्य से कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं



मोहिनी एकादशी व्रत की कथा

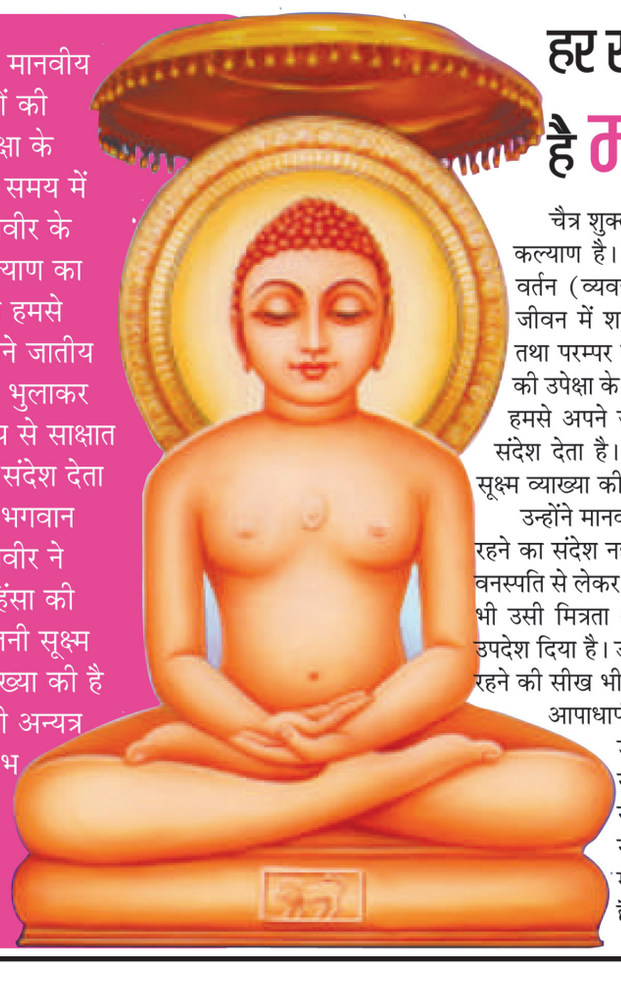
भद्रावती नाम की सुंदर नगरी थी। वहां के राजा धृतिमान थे। इनके नगर में धनपाल नाम का एक वैश्य रहता था, जो धन-धान्य से परिपूर्ण था। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। उसके पांच पुत्र थे। इनमें सबसे छोटा धृष्टबुद्धि था। वह पाप कर्मों में अपने पिता का धन लुटाता रहता था। एक दिन वह नगर वधू के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। इससे नाराज होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु-बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन-रात दु:ख और शोक में डूब कर इधर-उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के प्रभाव से महर्षि कौण्डिल्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। कौण्डिल्य गंगा में स्नान करके आए थे। धृष्टबुद्धि शोक के भार से पीडित हो मुनिवर कौण्डिल्य के पास गया और हाथ जोडकर बोला, ''ब्राहमण ! द्विजश्रेष्ठ ! मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो।'

कौण्डिल्य बोले:

वैशाख मास के शुक्लपक्ष में 'मोहिनी' नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। धृष्टबुद्धि ने ऋषि की बताई विधि के अनुसार व्रत किया। जिससे वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर श्री विष्णुधाम को चला गया।

हर समस्या का समाधान है महावीर दर्शन

मानवीय गुणों की उपेक्षा के इस समय में महावीर के कल्याण का दिन हमसे अपने जातीय भेद भुलाकर सत्य से साक्षात का संदेश देता है। भगवान महावीर ने अहिंसा की जितनी सूक्ष्म व्याख्या की है वैसी अन्यत्र दुर्लभ है।



चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को भगवान महावीर का जन्म कल्याण है। उनके सिद्धांत बताते हैं कि वर्तमान के वर्तन (व्यवहार) को किस प्रकार से रखा जाए कि जीवन में शांति, मरण में समाधि, परलोक में सद्गति तथा परम्पर से परमगति पाई जा सके। मानवीय गुणों की उपेक्षा के इस समय में महावीर के कल्याण का दिन हमसे अपने जातीय भेद भुलाकर सत्य से साक्षात का संदेश देता है। भगवान महावीर ने अहिंसा की जितनी सूक्ष्म व्याख्या की है वैसी अन्यत्र दुर्लभ है। उन्होंने मानव को मानव के प्रति ही प्रेम और मित्रता से रहने का संदेश नहीं दिया अपितु मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति से लेकर कीकीडे-मकोडे, पशु-पक्षी आदि के प्रति भी उसी मित्रता और अहिंसक विचार के साथ रहने का उपदेश दिया है। उनकी इस शिक्षा में पर्यावरण के साथ बने रहने की सीख भी है। आज जिस हिंसात्मक वातावरण और आपाधापी के बीच बच्चे बढ हो रहे हैं उसके कारण उनमें संयम का अभाव है। यह पीढी लक्ष्य से भटक रही है। ऐसे वातावरण में बडे हो रहे बच्चों से अपेक्षा रखना कि वे नैतिक राह पर चलेंगे ठीक नहीं। आज हमें समग्रता में महावीर की शिक्षाओं की बहुत जरूरत है ताकि हम इस धरा को सुंदर बना सकें।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

ममता को झटका, फ्रीज रहेंगे टीएमसी के 3 बैंक खाते



नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद ममता बनर्जी को लगातार झटके पर झटका मिल रहा है. कोलकाता हाईकोर्ट ने सोमवार (20 जुलाई) को तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी गुट को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से फ्रीज किए गए पार्टी के तीन बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया. ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के तीन बैंक खातों को फ्रीज किया था, जिनमें कुल 440.42 करोड़ रुपये जमा थे. यह कार्रवाई राज्य पुलिस की एफआईआर के आधार पर शुरू की गई जांच के तहत की गई. मामले में कथित वित्तीय गड़बड़ियों, अवैध रूप से धन जुटाने और पार्टी के कुछ बैंक खातों के जरिए संदिग्ध रकम के लेनदेन की जांच की जा रही है.पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, ईडी की शुरुआती जांच में सामने आया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच टीएमसी के बैंक खातों से करीब 160 करोड़ रुपये केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी एक अन्य इकाई को ट्रांसफर किए गए।

भारतीयों के लिए एडवाइजरी, ईरान की यात्रा टालें, तुरंत लौटें



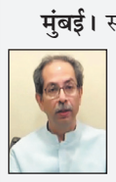
नई दिल्ली। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के बेहद हिंसक और अनियंत्रित होने के बाद भारत सरकार ने रविवार को एक बेहद महत्वपूर्ण और संशोधित ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थितियों का हवाला देते हुए सभी भारतीय नागरिकों को ईरान की अपनी आगामी यात्राओं को पूरी तरह से टालने की सख्त सलाह दी है. इसके साथ ही, जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान के भीतर मौजूद हैं, उन्हें जल्द से जल्द और अस्थायी रूप से ईरान छोड़ने का आग्रह किया गया है. दूतावास ने अपने बयान में कहा है कि पिछले कुछ दिनों में पूरे ईरान के भीतर अस्थिरता और हिंसा में भारी बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके चलते सुरक्षा वातावरण अत्यंत चिंताजनक हो गया है. भारतीय मिशन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि जो भारतीय नागरिक किसी भी उद्देश्य से ईरान जाने की योजना बना रहे हैं, वे सुरक्षा स्थिति में सुधार होने तक अपनी यात्रा को स्थगित कर दें।

भारत में पहली डेंगू वैक्सीन को मिली मंजूरी



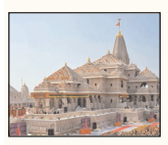
नई दिल्ली। हर साल जैसा ही मॉनसून दस्तक देता है, वैसे ही डेंगू का प्रकोप भी बढ़ने लगता है. बारिश के मौसम में डेंगू लाखों लोगों को अपनी चपेट में लेता है. इस बीच अब भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है. भारत में पहली बार डेंगू से बचाव के लिए एक वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है. इस वैक्सीन का नाम क्यूडेंगा है, जिसे जापान की फार्मा कंपनी Takeda ने तैयार किया है. भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने इसे 4 से 60 साल की उम्र के लोगों के लिए मंजूरी दी है. QDENGA भारत में मंजूर होने वाली पहली डेंगू वैक्सीन है. इसकी खासियत ये है कि इसे लगवाने से पहले ये टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होगी कि व्यक्ति को पहले कभी डेंगू हुआ है या नहीं. यानी ये वैक्सीन किसी को भी लगाई जा सकती है. अगर किसी को पहले डेंगू हो चुका है, उसे भी ये लगाई जा सकती है और अगर नहीं डेंगू नहीं हुई है तो भी इसे लगाया जा सकता है।

संसद मार्च के साथ जंतर-मंतर पर अनशन खत्म



मुंबई। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन कॉकरोच जनता पार्टी के चलो संसद मार्च के दौरान सेंट्रल दिल्ली में भारी हंगामा हुआ. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को संसद मार्ग पर पुलिस ने आंसू गैस और हल्का बल प्रयोग कर रोक दिया. कई जगह जाम लगा और सुरक्षा कड़ी कर दी गई. दिल्ली पुलिस के अनुसार, झड़प में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें 5 आईपीएस अधिकारी शामिल हैं. पुलिस ने करीब 100 लोगों को हिरासत में लिया और हिंसा व तोड़फोड़ के मामले दर्ज किए. पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े सोशल मीडिया हैंडल्स पर भ्रामक जानकारी फैलाने का भी आरोप लगाया, जबकि प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन को शांतिपूर्ण बताया. हालांकि जंतर-मंतर पर अनशन जरूर समाप्त हो गया है, लेकिन प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं. दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा।

राममंदिर चोरी मामलाः एसआईटी का हो पुनर्गठन- सुप्रीम कोर्ट



लखनऊ। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने जांच कर रही विशेष जांच टीम के पुनर्गठन पर विचार करने को कहा. कोर्ट ने कहा कि मामले को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए, जांच का मकसद सिर्फ सच्चाई तक पहुंचना और उसे सही दिशा में आगे बढ़ाना है. मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी. सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने जांच की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है. उन्होंने कहा कि अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जांच जारी होने के कारण इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी साझा नहीं की जा सकती. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि जांच के लिए बनाई गई एसआईटी में किन अधिकारियों को शामिल किया गया है. इस पर बताया गया कि टीम में दो आईएएस और एक आईजी स्तर के अधिकारी शामिल हैं।

नीट अभ्यर्थियों को प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी

आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई



नईदिल्ली। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) में धांधली और पेपर लीक के मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार का रुख पूरी तरह साफ कर दिया है। मंगलवार को एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने छात्रों को आश्वस्त किया कि उनके भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता व जवाबदेही तय की जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और कहा कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एनडीए की मंगल मिशन बैठक में बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों के हितों की रक्षा करने और परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

एनडीए बैठक में नेताओं को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि सरकार किसी भी गड़बड़ी के कारण छात्रों का भविष्य खराब नहीं होने देगी। उन्होंने कहा, हम छात्रों के भविष्य को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार पाए जाने वालों को कड़ी सज़ा दी जाएगी। नीट में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हें जेल भेजा जाएगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होना एक राष्ट्रीय चिंता का विषय है और इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी राज्यों से भी अपील की कि जहाँ कहीं भी ऐसी गड़बड़ियाँ सामने आएं, वहां बिना किसी ढिलाई के त्वरित व सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि योग्य उम्मीदवारों का समय और भविष्य प्रभावित न हो, इसके लिए पारदर्शी तरीके से दोबारा परीक्षा आयोजित कर परिणाम भी समय पर घोषित किए गए।

इस बीच, मंगलवार को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में आयोजित एनडीए की बैठक में कहा है कि सरकार नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक को लेकर चिंताओं के बीच छात्रों के साथ खड़ी है और अनियमितताओं में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आह्वान किया है।

आज एनडीए संसदीय दल की %मंगल मिलन% बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि सरकार छात्रों के साथ खड़ी है और पेपर लीक राष्ट्रीय चिंता का विषय है जिसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है और यह 13 अगस्त तक चलेगा।

मध्यप्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल पास

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बिल पास हो गया है। इस दौरान हंगामे के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जो हिंदू की बात करेगा, वही राज करेगा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि समानता हमारी संस्कृति का मूल है। भगवान की दृष्टि में सभी एक समान हैं, तो इंसानों द्वारा बनाए गए कानून में अलग-अलग व्यवस्था क्यों होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए।

सीएम यादव ने कहा, राम से रहीम तक, रविंद्र से रॉबिन तक, अमर से एंथोनी और अकबर तक, देश एक संविधान से चले। उन्होंने दावा किया कि समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद मध्यप्रदेश में भेदभाव से मुक्ति मिलेगी और राज्य गोवा, उत्तराखंड और असम के बाद इस दिशा में कदम बढ़ाने वाले चुनिंदा राज्यों में शामिल होगा। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों के खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के अलग। जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उनके वक्तव्य के दौरान विपक्ष का हंगामा जारी रहा, लेकिन मुख्यमंत्री ने सरकार का पक्ष विस्तार से सदन के सामने रख रहें हैं। सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में अलग-अलग मजहबी तौल कांटा नहीं होगा। सब एक ही बाट से तौले जाएंगे। इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष बताएं कि हम अपने दो बेटों को अलग-अलग दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं? समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पर सदन में वक्तव्य देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को सुझाव देने के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टिकरण और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती रही है तथा देश की जनता की पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के बाद मध्य प्रदेश में भेदभाव से मुक्ति मिलेगी।

सीजेपी प्रदर्शन पर कांग्रेस अध्यक्ष का केंद्र पर गंभीर आरोप

राज्यसभा में मेरा माइक बंद कर दिया गया: खड़गे

नईदिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को राजधानी में सीजेपी विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई की आलोचना की और आरोप लगाया कि विपक्ष को संसद में यह मुद्दा उठाने नहीं दिया गया।

पत्रकारों से बात करते हुए खड़गे ने आरोप लगाया कि पेपर लीक के कथित मामले को लेकर सीजेपी विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों पर पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। खड़गे ने कहा लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़ी गई और छात्रों की पिटाई की गई, जिससे कई लोग अस्पताल पहुंच गए। इस अन्याय, दमन और उन पर डाले जा रहे दबाव के खिलाफ, हमने उनकी ओर से आवाज़ उठाने के लिए संसद में समय मांगा था।

कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने यह मुद्दा उठाने की कोशिश की, तो उन्हें राज्यसभा में बोलने से रोका गया। उन्होंने कहा कि लेकिन जैसे ही मैं खड़ा हुआ और एक शब्द भी बोला, माइक बंद कर दिया गया। क्या यही लोकतंत्र है? अगर लोकतंत्र में आप बहस नहीं करना चाहते या हमारी बात नहीं सुनना चाहते, तो हम कहाँ जाएँ? देश के हर कोने से लाखों छात्र अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए आए हैं। खड़गे ने इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की विपक्ष की माँग दोहराई और कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस बहस का जवाब देना चाहिए। हम इस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। चर्चा के बाद, गृह मंत्री को बयान देना चाहिए। दूसरे फ्लोर लीडर्स को भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्यों को कमज़ोर करने का आरोप लगाते हुए खड़गे ने कहा, लोकतंत्र को खत्म करने की साज़िश चल रही है। यह अभूतपूर्व है – पिछले 60 सालों में मैंने किसी सरकार को इस तरह काम करते नहीं देखा। हम बस यही चाहते हैं कि चर्चा का मौका दिया जाए।



खरगे ने आगे कहा न्याय की मांग कर रहे छात्रों पर क्रूर लाठियों और आंसू गैस का इस्तेमाल क्यों किया गया? संसद को लगभग सील क्यों कर दिया गया और इंटरनेट क्यों बंद कर दिया गया? बार-बार पेपर लीक होने और लाखों युवाओं की पीड़ा के लिए कौन जिम्मेदारी लेगा?

राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गहरी पीड़ा व्यक्त करते हुए घोषणा की। उन्होंने अपना जन्मदिन न मनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही न्याय की मांग कर रहे युवाओं के खिलाफ बल प्रयोग की निंदा की है। मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पर एक पोस्ट में प्रशासनिक कार्रवाई पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, सोमवार को देश ने लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और सरकार की ओर से शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रदर्शन को कुचलते हुए देखा। न्याय की मांग कर रहे छात्रों की आवाजों को जवाब देने के बजाय बल प्रयोग से दबा दिया गया।

लोकतंत्र की जननी अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती। इन दुखद परिस्थितियों में, मैंने आज अपना जन्मदिन न मनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, %कांग्रेस के सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं, समर्थकों, शुभचिंतकों और हर उस नागरिक का मैं तहे दिल से आभारी हूं जिन्होंने मुझे शुभकामनाएं भेजी हैं। आपका स्नेह मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। लेकिन आज जश्न मनाने का दिन नहीं है। आज जवाबदेही तय करने का दिन है। लोकतंत्र को बहाल करो।

मल्लिकार्जुन खरगे ने लिखा, सरकार को संसद में इस मुद्दे पर तुरंत पूर्ण चर्चा की अनुमति देनी चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस मामले की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। 21वीं सदी की छात्र-केंद्रित परीक्षा प्रणाली होनी चाहिए जिसमें सुरक्षित डिजिटल प्रश्न बैंक और यादृच्छिक प्रश्नपत्र हों। एक स्वतंत्र और योग्यता आधारित शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, जिसमें शिक्षा पर अधिक खर्च हो और जो आरएसएस के राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त हो।

हॉस्पिटल पहुंचे राहुल-प्रियंका, घायल प्रदर्शनकारियों का जाना हाल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल ने उन छात्र प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की जो राजधानी में सीजेपी संसद विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई में घायल हो गए थे। कांग्रेस ने देश के युवाओं के साथ हुई इस बर्बरता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग की है। पार्टी ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग साफ है केंद्र सरकार कथित नीट पेपर लीक की जिम्मेदारी ले और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दें। कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कल युवाओं के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की बर्बरता और लाठीचार्ज में घायल हुए छात्रों से मुलाकात की। आज देश में छात्रों के भविष्य को कुचला जा रहा है और जो लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। इसके लिए नरेंद्र मोदी को माफ़ी मांगनी चाहिए।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज 23 जुलाई से



नईदिल्ली। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 23 जुलाई से शुरू होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज से पहले जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने बड़ा बयान देकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। रजा का मानना है कि यह सीरीज बिल्कुल भी एकतरफा नहीं होगी, क्योंकि दोनों टीमें बदलाव के दौर से गुजर रही हैं और दोनों के पास सीरीज जीतने का बराबर मौका है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहला टी20 मुकाबला 23 जुलाई, दूसरा टी20 मुकाबला 25 जुलाई, तीसरा टी20 मुकाबला 26 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा।

मीडिया से बातचीत में सिकंदर रजा ने कहा, दोनों देशों के पास यह सीरीज जीतने का बराबर मौका है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जिम्बाब्वे लगातार अच्छा और मनोरंजक क्रिकेट खेल रहा है, इसलिए यह सीरीज दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक रहने वाली है। उन्होंने आगे कहा, जहां तक जीत और हार का सवाल है, दोनों टीमों के पास सीरीज जीतने का समान अवसर है। रजा का मानना है कि सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि उनकी टीम भी ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है। भारत बदलाव के दौर से गुजर रहा है और किसी हद तक जिम्बाब्वे में भी बदलाव हो रहे हैं। इसलिए मुझे यह बिल्कुल भी एकतरफा सीरीज नहीं लगती।

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम हाल ही में आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज हार चुकी है। इंग्लैंड ने भारत को 4-0 से हराकर आईसीसी टी20 रैंकिंग में भी शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। ऐसे में टीम इंडिया इस सीरीज में वापसी के इरादे से उतरेगी।

भारतीय टीमः श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उपकप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रवि बिश्नोई।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 238 अंक टूटा निफ्टी 24,200 के नीचे

नईदिल्ली। घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में गिरावट देखने को मिली। पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के बीच निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया, जिसका असर बाजार पर साफ दिखाई दिया। आईटी और पीएसयू बैंकिंग शेयरों में बिकवाली के दबाव से प्रमुख सूचकांक लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स 238.41 अंक यानी 0.31 फीसदी की गिरावट के साथ 77,470.11 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 50 भी 51 अंक यानी 0.21 फीसदी टूटकर 24,187.70 के स्तर पर बंद हुआ। बड़े शेयरों में कमजोरी के बावजूद व्यापक बाजार का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा। निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.30 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 0.53 फीसदी चढ़कर बंद हुआ। इससे संकेत मिलता है कि निवेशकों की दिलचस्पी चुनिंदा मिड और स्मॉलकैप शेयरों में बनी रही।

बजाज ऑटो का पहली तिमाही का शुद्ध लाभ 42 प्रतिशत बढ़ा

मुंबई। बजाज ऑटो लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में एकल आधार पर शुद्ध लाभ 42 प्रतिशत बढ़कर 2,982.84 करोड़ रुपए रहा है। पुणे स्थित वाहन विनिर्माता कंपनी का वित्त वर्ष 2025-26 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में शुद्ध लाभ 2,095.98 करोड़ रुपए था। कंपनी ने मंगलवार को बयान में कहा कि समीक्षाधीन तिमाही में उसकी परिचालन आय 37% बढ़कर 17,243.72 करोड़ रुपए हो गई जो एक वर्ष पहले की समान अवधि में 12,584.45 करोड़ रुपए थी। एकीकृत आधार पर कंपनी का शुद्ध लाभ 46% बढ़कर 3,225.63 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 2,210.40 करोड़ रुपए था। कंपनी की एकीकृत कुल परिचालन आय 13,642.33 करोड़ रुपए से सालाना आधार पर 64% बढ़कर 22,376.69 करोड़ रुपए हो गई।

पेटीएम ने वॉलेट सेवा फिर शुरू करने आरबीआई से मांगा लाइसेंस

नईदिल्ली। करीब डेढ़ साल पहले रिजर्व बैंक की कार्रवाई के बाद झटका झेलने वाली पेटीएम अब अपने डिजिटल वॉलेट कारोबार की वापसी की तैयारी में है। कंपनी ने अपनी सहयोगी इकाई पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। यदि यह लाइसेंस मिल जाता है, तो पेटीएम एक बार फिर अपने ग्राहकों को डिजिटल वॉलेट की सुविधा दे सकेगी। कंपनी का मानना है कि इससे ग्राहकों को भुगतान के अधिक विकल्प मिलेंगे और उसके पेमेंट कारोबार को भी नई गति मिलेगी। पीपीआई एक डिजिटल वॉलेट सुविधा है, जिसमें यूजर पहले पैसे जमा करते हैं और बाद में इन पैसों से पेमेंट या खरीदारी कर सकते हैं। पीपीआई लाइसेंस मिलने के बाद पेटीएम जैसी कंपनियां अपनी वॉलेट सेवा खुद चला सकती हैं।

थोक मूल्य सूचकांक की जगह आएगा उत्पादक मूल्य सूचकांक

नई दिल्ली। भारतीय अर्थव्यवस्था में महंगाई के आकलन को अधिक पारदर्शी और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ा नीतिगत कदम उठाया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 15 जून को देश का पहला उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआई) डेटा जारी करने के साथ ही थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने इस बड़े बदलाव के लिए पांच साल का ट्रांजिशन पीरियड तय किया है। इस कदम से देश के नीतिगत फैसलों, औद्योगिक आंकड़ों और कॉर्पोरेट जगत के कमर्शियल अनुबंधों पर गहरा असर पड़ेगा। डब्ल्यूपीआई थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को मापता है, जबकि पीपीआई फैक्ट्री गेट पर उत्पादकों द्वारा प्राप्त कीमतों को दर्शाता है।

विक्रम-1 की सफलता के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ा भारत का दबदबा

विनोद कुमार विक्की

निजी अंतरिक्ष प्रक्षेपण कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा विकसित विक्रम-1 की सफलता के पश्चात भारत अमेरिका और चीन के बाद निजी क्षेत्र में आर्बिटल स्थापित करने वाला विश्व का तीसरा देश बन चुका है।18 जुलाई को श्री हरिकोटा से प्रक्षेपण के पांचवें चरण में 450 किमी की ऊंचाई पर पृथ्वी के निचली कक्षा में उपग्रह उपकरण को स्थापित कर विक्रम-1 ने विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। इस सफलता के साथ भारत दुनिया में लघु उपग्रह के प्रक्षेपण को पूर्ण करने में नये विकल्प के रूप में उभरा है।

मानव सभ्यता के विकास का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर प्रभुत्व स्थापित किया, उसी ने विश्व मंच पर नेतृत्व की भूमिका निभाई। इक्कीसवीं सदी में यह प्रतिस्पर्धा धरती की सीमाओं से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुँच चुकी है। अंतरिक्ष विज्ञान अब केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा का विषय नहीं रह गया है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, संचार, मौसम पूर्वानुमान, कृषि, आपदा प्रबंधन, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और वैश्विक कूटनीति का भी महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। ऐसे समय में भारत ने अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा, स्वदेशी तकनीक और दूरदर्शी नीतियों के बल पर जिस प्रकार अंतरिक्ष क्षेत्र में निरंतर सफलता अर्जित की है, वह न केवल प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का विषय है, बल्कि यह संकेत भी है कि भारत अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।

भारत की पहली निजी अंतरिक्ष प्रक्षेपण कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा विकसित विक्रम-1 प्रक्षेपण यान की सफलता इस यात्रा का एक ऐतिहासिक पड़ाव है। पूर्णत: स्वदेशी डिज़ाइन और आधुनिक तकनीक से निर्मित इस प्रक्षेपण यान ने यह सिद्ध कर दिया कि



भारत की निजी कंपनियाँ भी अब वैश्विक स्तर पर अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकसित करने में सक्षम हैं। विक्रम-1 ने पृथ्वी की निचली कक्षा में सफलतापूर्वक उपग्रह उपकरण स्थापित कर न केवल अपनी तकनीकी क्षमता का परिचय दिया, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत अब लघु उपग्रह प्रक्षेपण के वैश्विक बाज़ार में एक मजबूत और विश्वसनीय विकल्प बनकर उभर रहा है।

यह उपलब्धि केवल एक रॉकेट की सफलता भर नहीं है, बल्कि भारत की बदलती अंतरिक्ष नीति और वैज्ञानिक आत्मविश्वास का प्रतीक भी है। वर्षों तक अंतरिक्ष गतिविधियाँ मुख्यत: सरकारी संस्थानों तक सीमित थीं, किंतु अब निजी क्षेत्र के लिए दरवाज़े खुलने के बाद भारतीय स्टार्टअप नई ऊर्जा और नवाचार के साथ इस क्षेत्र में उतर रहे हैं। इससे अनुसंधान, रोजगार, निवेश और तकनीकी विकास के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ती निजी भागीदारी भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अधिक सक्षम बना रही है।

वर्ष 2013 में प्रक्षेपित मंगलयान (मार्स ऑर्बिटर मिशन) ने भारत को पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुँचने वाला विश्व का पहला देश बना दिया। यह उपलब्धि वैज्ञानिक दृष्टि से जितनी महत्वपूर्ण थी, उतनी ही आर्थिक दृष्टि से भी, क्योंकि अत्यंत कम लागत में इस मिशन की सफलता ने भारत की दक्षता का विश्वभर में लोहा मनवाया।

इसी प्रकार PSLV-C37 द्वारा एक ही मिशन में 104 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण विश्व रिकॉर्ड बना। इस उपलब्धि ने भारतीय प्रक्षेपण प्रणाली की विश्वसनीयता और क्षमता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई। इसके बाद चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। भारत ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बना। इस उपलब्धि ने न केवल भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा को विश्व के सामने स्थापित किया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि भारत जटिलतम अंतरिक्ष अभियानों को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम है।

इसी क्रम में आदित्य-एल1 मिशन भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान को नई दिशा प्रदान कर रहा है। सूर्य के अध्ययन के लिए समर्पित यह भारत का पहला मिशन है, जो सौर गतिविधियों, अंतरिक्ष मौसम और पृथ्वी पर उनके प्रभावों को समझने में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध करा रहा है।

भाजपा कोर कमेटी की बैठक, मुख्यमंत्री साय हुए शामिल

पिछले कार्यों की समीक्षा और आगामी कार्यों पर हुई चर्चा

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव, वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों और कोर कमेटी के सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों, राजनीतिक रणनीति और आगामी कार्ययोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक को पार्टी की आगामी रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की मौजूदगी में हुई इस बैठक में सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय को लेकर भी चर्चा हुई। पार्टी पदाधिकारियों ने प्रदेश में संगठन को और मजबूत करने तथा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर विचार-विमर्श किया।



बैठक में वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों ने प्रदेश की राजनीतिक स्थिति, संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों को लेकर अपने सुझाव रखे। बीजेपी कोर कमेटी समय-समय पर प्रदेश में पार्टी की दिशा और रणनीति तय करने के लिए बैठक करती है। इस बैठक में भी कई महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन किया गया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए पार्टी संगठन की भूमिका पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने संगठन को जमीनी स्तर पर सक्रिय रखने और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संवाद बनाए रखने पर जोर दिया।

आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी की बैठक आयोजित की गई है। भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक में जो पिछले समय 12 साल बेमिसाल के कार्यक्रम लगातार सभी स्थानों पर सभी जिलों में संपर्क अभियान चलाने के साथ ही सेमिनार और संगोष्ठी आयोजित किया गया था। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक ले जाने के जो कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। उस कार्यक्रम की इस बैठक में समीक्षा की गई है। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 वीं जयंती को उनके बलिदान दिवस के रूप में 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक मनाया गया इसकी भी समीक्षा इस बैठक में की गई- नवीन मारकंडे, भाजपा प्रदेश महामंत्री

भाजपा प्रदेश महामंत्री नवीन मारकंडे ने बताया कि 25 जून को आपातकाल दिवस मनाया गया। उसके उपलक्ष में जो भी कार्यक्रम आयोजित किए गए थे उनकी भी समीक्षा इस बैठक में की गई। इसके साथ ही अब तक जो कार्यक्रम लगातार आयोजित हुए हैं। उसकी भी समीक्षा की गई। आगामी कार्यक्रम संत रविदास जी की जयंती फरवरी महीने की मांघी पूर्णिमा तक चलना है तो इस कार्यक्रम की शुरुआत 23 जुलाई से करेंगे।

वीन मारकंडे ने बताया, एक बड़ी कार्यशाला आयोजित की जाएगी। संत रविदास जी की यह 650 वीं जयंती होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वाराणसी में संत रविदास जी की भव्य स्मारक तैयार किया जा रहा है। वहां से हमारी टीम 27 जुलाई को मिट्टी और पानी लाकर छत्तीसगढ़ के सभी देवी स्थलों यानी मंदिरों में लेकर जाएंगे। वहां दर्शन करेंगे। एक यह कार्यक्रम लगातार चलेगा। इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा और वंदे मातरम अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। इन दोनों कार्यक्रमों की बैठक में समीक्षा के साथ ही और तैयारी पर चर्चा हुई। बीजेपी लगातार अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। बैठक में मंत्रियों और कोर कमेटी सदस्यों की मौजूदगी से साफ है कि पार्टी सरकार और संगठन के बीच तालमेल को प्राथमिकता दे रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने के बाद यह बैठक राजनीतिक और संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

मुख्यमंत्री से अभा सेवाओं में चयनित अभ्यर्थियों ने की सौजन्य मुलाकात



रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ से अखिल भारतीय सेवाओं में चयनित अभ्यर्थियों ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनसे जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं में चयनित होना केवल अभ्यर्थियों और उनके परिवार की नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का अवसर है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सेवा समाज और राष्ट्र के निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम है तथा इसमें कार्य करने वाले अधिकारियों को संवेदनशीलता, ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों से कहा कि उन्हें लोगों की सेवा का जो अवसर मिला है, वह ईश्वर का आशीर्वाद और समाज का विश्वास है। इस अवसर का उपयोग आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने तथा प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने में युवा प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी चयनित अभ्यर्थी अपनी प्रतिभा, कार्यकुशलता और सेवा भावना से छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

इस अवसर पर चयनित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से अपने अनुभव साझा किए तथा उनके मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। सौजन्य मुलाकात के दौरान अखिल भारतीय सेवाओं में चयनित अभ्यर्थियों में सुष्मिता सिंह, वैभवी अग्रवाल, दर्शना सिंह बघेल, रौनक अग्रवाल, अजय गुप्ता, अंकित सकनी, डायमंड ध्रुव एवं संजय डहरिया सहित उनके परिजन उपस्थित थे।

जनरेशन कंपनी के गारे पेलमा सेक्टर-III कोयला खदान को मिला राष्ट्रीय स्तर पर 5-स्टार रेटिंग

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी की गारे पेलमा सेक्टर-III कोयला खदान को भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा 5-स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। जनरेशन कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आयोजित स्टार रेटिंग मूल्यांकन में 92 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए यह उपलब्धि अर्जित की है।

भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार गारे पेलमा सेक्टर-द्वद्वद्व कोयला खदान ने देश की 206 ओपनकास्ट कोयला खदानों में राष्ट्रीय स्तर पर 20वां स्थान प्राप्त किया है। साथ ही यह गारे पेलमा कोलफील्ड की सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाली खदानों में भी शामिल है। पावर कंपनीज के अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह ने इस उपलब्धि पर अधिकारी-कर्मचारियों को बधाई दी है। जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक संजीव कुमार कटियार ने कहा कि इसके साथ ही केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीनस्थ खान सुरक्षा महानिदेशालय ने भी जनरेशन कंपनी के गारे पेलमा खदान को पुरस्कृत किया है। वार्षिक कोयला खान सुरक्षा पखवाड़ा 2025 में इसे सात राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए थे। साथ ही पिछले पांच वर्षों से खदान संचालन में सुरक्षा संबंधी मापदण्डों के पालन में उम्दा प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि फाइव स्टार रेटिंग मिलना सीएसपीजीसीएल की उत्कृष्ट कार्य संस्कृति एवं सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह उपलब्धि भविष्य में भी कंपनी को राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन बनाए रखने तथा कोयला खनन के प्रत्येक क्षेत्र में नए मानक स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगी।

देश की सभी कोयला खदानों का मूल्यांकन खनन संचालन, पर्यावरण संरक्षण, आधुनिक तकनीक का उपयोग, आर्थिक प्रदर्शन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, श्रमिक कल्याण तथा सुरक्षा एवं संरक्षा सहित सात प्रमुख मानकों पर किया जाता है। इन सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर स्टार रेटिंग प्रणाली तय की जाती है।

शराब की ओवर रेटिंग में पूरी सरकार संलिप्त है : दीपक बैज

रायपुर। प्रदेश में शराब धड़ल्ले से ओवर रेट में बेची जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि इस पूरे खेल को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। शराब की ओवर रेटिंग सरकार में बैठे हुए लोग करा रहे है। हर ब्रांड की शराब में 10 से 60 रू. तक प्रति बोतल वसूला जा रहा था। शराब के काऊंटर में बैठे लोग दावा कर रहे है कि शराब का पैसा ऊपर तक जा रहा था। यह मामला मीडिया मे आया और जनता ने विरोध किया तब जाकर कुछ अधिकारियों को सस्पेंड करने की कार्यवाही की गयी। अधिकारी तो सरकार के निर्देश पर काम कर रहे थे उन्हे बलि का बकरा बना दिया गया।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकारी आंकड़ों में प्रतिदिन शराब का विक्रय 28 लाख 65 हजार बोतल है, हर



बोतल में 10 से 60 रू. अधिक वसूला जा रहा है, 4 करोड़ 29 लाख प्रतिदिन अवैध वसूली, महिनें का 129 करोड़, 1548 करोड़ सालाना, विगत ढाई साल में 3870 करोड़ का शराब ओवर रेटिंग घोटाला इस सरकार ने किया गया है।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पूरे प्रदेश में संगठित शराब घोटाला चल रहा। हजारों करोड़ रूपये वसूली हो रही है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी तब पता चलेगा कितने बड़े-बड़े लोग शामिल है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि भाजपा के सरकार में शराब घोटाला हुआ है ईडी, सीबीआई जांच करने से क्यों घबरा रही है ?प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार नकली मिलावटी और अवैध शराब को बिकवा रही है। रायगढ़ में नकली शराब की बाटलिंग हो रही थी। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा में नकली होलो ग्राम वाली शराब पकड़ाये।

राजनांदगांव अवैध शराब का केन्द्र बन गया है। बलरामपुर के सरकारी शराब दुकान में बियर के बोतल में गंदा पानी मिला, जगदलपुर में दर्जनों पेटी अवैध शराब पकड़ाई, मध्यप्रदेश से जगदलपुर तक कई जिलों की सीमा पार कर अवैध शराब की निर्बाध सप्लाई बिना सत्ता के संरक्षण के संभव नहीं है। सरकारी शराब दुकानों में दो गल्ले चल रहे है। बलरामपुर के सरकारी शराब दुकान में जो बियर की बोतल में गंदा पानी निकल रहा है।

बीरगांव ननिका सिंगल यूज़ प्लास्टिक के विरुद्ध अभियान, वसूला जुर्माना



बीरगांव। आयुक्त युगल किशोर उर्वशा के निर्देशन में नगर पालिक निगम द्वारा शहर में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग एवं भंडारण की जांच की गई।निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 3,400 का जुर्माना वसूला गया। साथ ही संबंधित व्यापारियों को भविष्य में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने तथा पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए समझाइश दी गई।नगर पालिक निगम ने नागरिकों एवं व्यापारियों से अपील की है कि वे प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग पूर्णत: बंद करें तथा स्वच्छ एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपना सहयोग प्रदान करें। निगम द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

डुंडा बोरिया के देवी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट में मिली गंदगी, 10 हजार का जुर्माना

रायपुर। नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 10 स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वच्छता से सम्बंधित प्राप्त जनशिकायत की वस्तुस्थिति की जानकारी लेने जोन 10 क्षेत्र अंतर्गत डुंडा बोरिया में स्थित देवी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट की स्वच्छता व्यवस्था का औचक निरीक्षण नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर जोन 10 जोन कमिश्नर मोनेश्वर शर्मा के मार्गनिर्देशन में किया गया.



स्वच्छता व्यवस्था के औचक निरीक्षण के दौरान गन्दगी फैलाया जाना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम का उल्लंघन करना पाया गया. प्राप्त जनशिकायत स्थल पर पूरी तरह सही मिलने पर निर्देशानुसार जोन स्वास्थ्य अधिकारी अमित बेहरा एवं स्वच्छता निरीक्षक यशवंत बेरिहा द्वारा देवी स्वीट्स डुठ्ठस रेस्टोरेंट के सम्बंधित संचालक को भविष्य के लिए कड़ी चेतावनी देते हुए स्वच्छता दीदियों की स्थल पर उपस्थिति में तत्काल 10 हजार रूपये का ई जुर्माना किया और प्राप्त जनशिकायत का जोन के स्तर पर नगर निगम जोन 10 स्वास्थ्य विभाग द्वारा त्वरित निदान किया गया.

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 81वें दौर का शुभारंभ

रायपुर। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय , भारत सरकार के मार्गदर्शन में तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 81वें दौर के अंतर्गत प्रवासन सर्वेक्षण , अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण तथा कृषि परिवारों का स्थिति आकलन सर्वेक्षण का क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्य जुलाई 2026 से प्रारंभ कर दिया गया है। यह सर्वेक्षण जून 2027 तक संचालित किया जाएगा। इन तीनों राष्ट्रीय महत्व के सर्वेक्षणों का उद्देश्य राज्य एवं देश की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों से संबंधित विश्वसनीय आंकड़ों का संकलन करना है, ताकि साक्ष्य-आधारित नीतियों, योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों के निर्माण में इनका प्रभावी उपयोग किया जा सके।प्रवासन सर्वेक्षण के माध्यम से व्यक्तियों एवं परिवारों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के कारणों, प्रवास की अवधि, रोजगार, शिक्षा, विवाह तथा अन्य सामाजिक-आर्थिक कारकों से संबंधित जानकारी एकत्रित की जाएगी। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े देश में प्रवासन की प्रवृत्तियों तथा उसके सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों को समझने में महत्वपूर्ण आधार प्रदान करेंगे। खिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण के तहत परिवारों की ऋणग्रस्तता, ऋण के स्रोत, निवेश के स्वरूप, परिसंपत्तियों तथा देनदारियों से संबंधित जानकारी संकलित की जाएगी। इससे नागरिकों की वित्तीय स्थिति, ऋण तक पहुंच तथा वित्तीय समावेशन के स्तर का समग्र आकलन किया जा सकेगा।

केंद्रीय बैठक में शामिल हुए छत्तीसगढ़ समाज के पदाधिकारी



रायपुर। 19 जुलाई को प्रयागराज के होटल कन्हा श्याम में आयोजित अखिल भारतीय अग्रहरि समाज के 20वीं कार्यकारिणी की बैठक में छत्तीसगढ़ की 16 सदस्यों की टीम ने शिरकत किया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के के अग्रहरि बिलासपुर एवं रमाशंकर अग्रहरि मनेंद्रगढ़, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध अग्रहरि करगी रोड ,छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष सुजीत अग्रहरि दुर्ग , मनोज केशव अग्रहरि प्रदेश महामंत्री एवं राष्ट्रीय प्रचार मंत्री(बेलगहना) राजेश अग्रहरि जी राजनंदगांव ,डॉ निर्मला गुप्ता जी दुर्ग ,एडवोकेट राधेश्याम अग्रहरि जी रायपुर ,सौरभ गुप्ता जी रायपुर ,अंकित शाह जी भिलाई , एडवोकेट मनोज अग्रहरि करगी रोड ,देवेंद्र अग्रहरि जी बिलासपुर ,राजेश अग्रहरि जी करगी रोड ,संतोष अग्रहरि जी सूरजपुर ,लखन अग्रहरि जी अंबिकापुर की सशक्त उपस्थिति में छत्तीसगढ़ अग्रहरि समाज के कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की जानकारी महामंत्री मनोज गुप्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया।

हस्तशिल्प विकास बोर्ड की अध्यक्ष शालिनी राजपूत वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम में हुई शामिल



रायपुर। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत शासकीय विज्ञान महाविद्यालय दुर्ग में आयोजित वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों से दैनिक जीवन में स्थानीय स्तर पर निर्मित ग्रामोद्योग एवं हस्तशिल्प उत्पादों को अपनाने तथा उनके उपयोग को बढ़ावा देने की अपील की। श्रीमती शालिनी राजपूत ने कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए विभिन्न हस्तशिल्प स्टॉलों का अवलोकन किया तथा स्थानीय शिल्पकारों से संवाद कर उनके कार्यों, उत्पादों एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों के अधिकाधिक उपयोग से न केवल पारंपरिक कला एवं संस्कृति का संरक्षण होगा। बल्कि शिल्पकारों और ग्रामीण उद्यमियों को भी आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर हस्तशिल्प प्रबंधक श्री सी.एस. केहरि व अन्य अधिकारी-कर्मचारी, शिल्पकार एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

स्मार्ट मीटर पर कांग्रेस फैला रही भ्रमः सवन्नी

रायपुर। स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस द्वारा किए जा रहे विरोध और सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावों को खारिज करते हुए क्रेडा के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सवन्नी ने कहा है कि स्मार्ट मीटर बिजली उपभोक्ताओं को अधिक सशक्त, जागरूक और सुविधाजनक व्यवस्था उपलब्ध कराने का माध्यम है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जनता के बीच झूठा भ्रम फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर परियोजना की शुरुआत और इसके टेंडर कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही स्वीकृत किए गए थे। सवन्नी ने कहा कि भारत सरकार ने 20 जुलाई 2021 को रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत पूरे देश में स्मार्ट मीटर योजना शुरू की थी और 29 जुलाई 2021 को इसकी संचालन संबंधी गाइडलाइन जारी की गई थीं। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में इस परियोजना की डीपीआर 13 जुलाई 2022 को मंजूर हुई, जबकि 22 सितंबर 2022 को टेंडर जारी किए गए। जून 2023 में कांग्रेस सरकार के दौरान अंबिकापुर, बिलासपुर, रायगढ़ तथा रायपुर क्षेत्र के लिए कंपनियों का चयन किया गया और अक्टूबर 2023 में दुर्ग, राजनांदगांव तथा जगदलपुर क्षेत्र के लिए भी एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी गई।



प्रिपेड बिजली कनेक्शन, बिलिंग सिस्टम को लेकर दी जानकारी

प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में 1 अगस्त से होगा लागू

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के ऊर्जा विभाग ने एक आदेश जारी कर राज्य के सरकारी कार्यालयों में एक अगस्त से प्रिपेड बिलिंग सिस्टम प्रारंभ करने का निर्देश दिया है। वर्तमान में बकाया बिजली बिल के भुगतान को लेकर जरुरी दिशा निर्देश भी दिया है। प्रिपेड बिलिंग सिस्टम को किस तरह रखना है और भुगतान की प्रक्रिया क्या होगी, इसे विभाग प्रमुख को तय करने की छूट दी है।

उर्जा विभाग ने जारी आदेश में लिखा है, प्रदेश के शासकीय कार्यालयों, भवनों के विद्युत कनेक्शन में 01 अगस्त 2026 से प्रिपेड बिलिंग प्रारंभ किये जाने हेतु जारी मार्गदर्शिका के परिपेक्ष्य में एवं उक्त के संबंध में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों,शंकाओं के समाधान हेतु बुधवार, 15 जुलाई 2026 को शाम 4:30 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओरिएंटेशन कार्यशाला आयोजित



की गई थी।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार दवारा लागू की गई आरडीएसएस आरडीएसएस योजना हेतु जारी दिशा-निर्देशों में स्मार्ट मीटरिंग द्वारा प्री-पेड बिलिंग अनिवार्य किए जाने का प्रावधान है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियमित रूप से योजना की समीक्षा की जा रही है तथा उक्त शर्त को पूर्ण नहीं किए जाने के कारण विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय अनुदान की राशि में से केवल दो तिहाई राशि जारी की गई है, एक तिहाई राशि को रोक लिया गया है। विद्युत मंत्रालय द्वारा 21 मई 2026 को संपन्न समीक्षा बैठक में 1 जुलाई 2026 से शासकीय कनेक्शनों में प्री-पेड बिलिंग अनिवार्य रूप से प्रारंभ करने के निर्देश दिये गये है।

दो चरणों में प्रारंभ होगा काम

कुल शासकीय कनेक्शनकी संख्या 1,65,727 है। इसमें 1,43,800 कनेक्शनों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

राज्य शासन द्वारा दो चरणों में सभी शासकीय कार्यालयों में प्री-पेड स्मार्ट मीटर की स्थापना कर प्री-पेड बिलिंग करने का निर्णय लिया गया है। जिसके तहत प्रथम चरण में 1 अगस्त 2026 से विकासखण्ड एवं उच्च स्तर तक के सभी शासकीय कनेक्शनों का स्मार्ट मीटर के माध्यम से प्री-पेड बिलिंग किया जावेगा एवं इसके उपरांत दिवतीय चरण में विकासखण्ड स्तर से निम्न स्तर के कार्यालयों में प्री-पेड बिलिंग का कार्य किया जाएगा।

ऐसे होगा लागू

प्री-पेड बिलिंग प्रारंभ किये जाने के पूर्व समस्त कनेक्शनों की बकाया राशि निरंक किये जाने का प्रावधान है। परन्तु राज्य सरकार द्वारा 1 अगस्त 2026 से प्री-पेड बिलिंग पद्धति सुचारू रूप से लागू हो, यह सुनिश्चित करने के लिये दिनांक 30 जून 2026 की स्थिति में विभागवार बकाया राशि को फ्रीज कर इस राशि को आगामी 04 तिमाही में समान किश्तों में भुगतान किए जाने की व्यवस्था की जाए।. शासकीय विभागों के विरुद्ध मार्च 2026 की स्थिति में कल लंबित बकाया राशि 2883.42 करोड है, अप्रैल से जून 2026 का अनुमानित डिमांड जोड़ने पर जून 2026 की स्थिति में अनुमानित बकाया राशि ? 3432.64 करोड़ हो जायेगी।

रिटायर होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों की सूची विभागवार अपडेट करने के निर्देश

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील ने आज मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के समस्त विभागों के भार साधक सचिवों की बैठक ली। बैठक में विभागों के महत्वपूर्ण कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा है कि सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विभिन्न प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया दो वर्ष से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए है कि सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारियों की सूची विभागवार अद्यतन कर ली जाए।मुख्य सचिव ने विभागीय सचिवों को उनके विभाग की



योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए है। बैठक में ई-ऑफिस, आधार बेस अटेंडेंस, लोक सेवा गारंटी, सूचना के अधिकार, सुघ्घर छत्तीसगढ़, नियद नेल्लानार योजना, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति, डी रेगुलेशन ई-गजट, सेवा सेतु, ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं, पीएम सूर्य घर बिजली सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली गई। मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि आई-गॉट के तहत विभागवार चिन्हित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग की जाये। अधिकारी-कर्मचारियों को आई-गॉट के तहत विभाग की आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण दिलाने कहा है। विभागों की योजनाओं एवं सेवाओं को ऑनलाइन किया जाए।बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, विधि एवं विधायी विभाग की प्रमुख सचिव सुषमा सावंत मौजूद रहे।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.